कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

ज्येष्ठ–आषाढ़ 2083, जुलाई 2026

इसरो वैज्ञानिकों के त्यागपत्र

अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र को लाभ

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी समावेशी

बेंगलुरू, 12 जुलाई 2026

सचित्र झलक

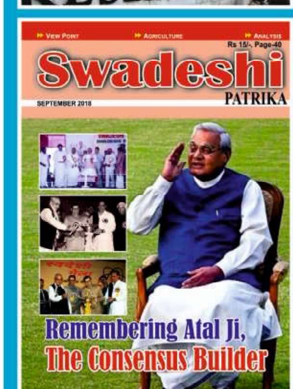

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI
Patrika

स्वदेशी
पत्रिका

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–34, अंक–7

ज्येष्ठ–आषाढ़ 2083 जुलाई 2026

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

इसरो वैज्ञानिकों के त्यागपत्र

अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र को लाभ

डॉ. अश्वनी महाजन

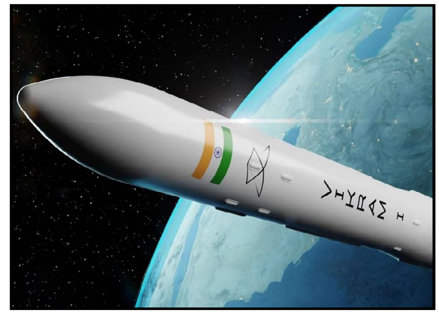

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा–2
स्वदेशी की ताकत से मिली स्काईरूट को कामयाबी ...... *अनिल तिवारी*

10 विवेचन
देशी, स्वदेशी और विदेशी ...... *डॉ. धनपत राम अग्रवाल*

14 डिजिटल कंटेंट क्रिएशन
गांवों में भी बढ़ी 'फोटो–एल्बम' की जगह 'रील्स' की मांग ...... *शिवनंदन लाल*

16 विश्व जनसंख्या दिवस
बूढ़ी होती दुनिया, सिकुड़ते देश, और भारत की चुनौती ...... *प्रो. दीपक शर्मा*

18 विचार
क्वांटो क्रॉस–करेंसी डेरिवेटिव ...... *विनोद जौहरी*

20 व्यापार
भारत–अमेरिका ट्रेड डील – सुस्त चाल के दाव–पेंच ...... *दुलीचंद कालीरमन*

22 आर्थिकी
संतुलित होता असंतुलित विकास ...... *मुनि शंकर पाण्डेय*

24 नीति
भारत–जापान की नई रणनीतिक साझेदारी से बदलेंगे एशिया के शक्ति समीकरण ...... *अजय कुमार*

26 डिजिटल डेटा सुरक्षा
डिजिटल डेटा सुरक्षा के लिए बने कारगर कानून ...... *डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र*

28 भारतीय रेल
भारत में चली पहली हाइड्रोजन ट्रेन ...... *गौरी तिवारी*

30 मुद्दा
विदेश से भारत की संप्रभुता–सुरक्षा के खिलाफ डिजिटल वार ...... *संजय सक्सेना*

32 स्वास्थ्य
नशा मुक्ति उपचारः स्वस्थ जीवन की ओर लौटने का मार्ग ...... *डॉ. विजय गर्ग*

34 विभूति
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन और बलिदान से देश को दिए प्राण ...... *हेमेन्द्र क्षीरसागर*

पाठकनामा

भूमि सुपोषण अभियान

भूमि सुपोषण अभियान का शुभारंभ वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया था, यह एक जन जागरण अभियान है, यह अभियान 2020 से प्रत्येक वर्ष वर्षप्रतिपदा से प्रारंभ होकर अक्षय तृतीया तक सम्पूर्ण भारतवर्ष में चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत कुपोषित हो रही कृषि भारतभूमि को पुनः सुपोषित बनाने और उसमें मानव, पशु–पक्षियों एवं प्रकृति के योगदान और भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर जन जागरण का कार्य किया जाता है। भूमि कुपोषण की वजह से आज के इस आधुनिक युग में मानव जीवन पर कई तरीके के संकट आ रहे है, व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता, फिर भी कई बीमारियों से ग्रसित है (मुख्यतःकैंसर), उसका मुख्य कारण है रसायनयुक्त भोजन। जिसे ग्रहण करने के उपरांत हमारा शरीर धीरे–धीरे रोगग्रसित होकर औषधियों के सहारे कट रहा है। किसान अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, जिससे उसी उर्वरक का सूक्ष्म भाग उत्पादित अनाज के माध्यम से हमारे पास जाता है और जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते है। अधिक रसायनों के उपयोग से हमारी भूमि माता बीमार हो रही है और बीमार भूमि स्वस्थ्य उत्पाद कैसे दे सकती है?

रसायनयुक्त उत्पाद को छोड़कर प्राकृतिक एवं पारंपरिक कृषि की ओर पुनः वापसी के लिए इस अभियान को चलाया गया है। वर्ष 1966 हरित क्रांति से पहले किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता था, उस समय इतनी भयंकर बीमारियां भी नहीं होती थी। अब हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द पुनः प्राकृतिक उत्पाद अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रसायन–मुक्त खेती को बढ़ावा देने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और किसानों की लागत कम करने के लिए एक योजना बनायी है। इस योजना को 25 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई थी, जिसका कुल बजट 2,481 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। भूमि सुपोषण अभियान के अंतर्गत भूमि पूजन कार्यक्रम 2.5 लाख से भी अधिक स्थानों पर किया जा चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को पुनः अपनी धरती माता के प्रति जागरूक करना है।

किशन शर्मा, अक्षय कृषि परिवार, नई दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

भारत और न्यूज़ीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है और द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति देगा।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

2047 तक 'विकसित भारत' के विज़न को साकार करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इस सफ़र में 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' एक अहम स्तंभ के तौर पर काम करेगा।

जे.पी. नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री, भारत

हाइड्रोजन एक नई ऊर्जा और नया ईंधन है। परिवहन में इस ईंधन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, भारत में इसकी तकनीक कैसे विकसित की जाए और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत इसे एक स्वदेशी तकनीक कैसे बनाया जाए? यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अश्वनी वैष्णव, रेलमंत्री, भारत

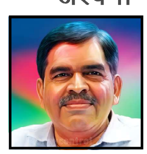

भारतीय वैज्ञानिक अमरीका के अंतरिक्ष संस्थान 'नासा' में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारतीय डॉक्टर और भारतीय अध्यापक, सभी भारत के ब्रांड एंबेसेडर बनकर दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीयों की प्रतिभा का उपयोग भारत में ही पूर्ण रूप से नहीं हो पाया।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

युद्ध से आई ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रयासों में तेजी

लगभग साढ़े तीन महीने के खाड़ी युद्ध के बाद अमरीका और ईरान में शांति समझौते के फलस्वरूप स्ट्रेट ऑफ़ हार्मुज, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की आवाजाही होती है, अब खुल चुका है। गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ़ हार्मुज के बंद होने के कारण जहां तेल की आवाजाही बाधित हुई थी, तेल की कीमतें भी भीषण रूप से बढ़ गई थी। कच्चे तेल की कीमत, जो युद्ध से पहले मात्र 70 से 80 डालर प्रति बैरल के आस–पास थी, इस दौरान एक बार बढ़कर 126 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। हालांकि तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव आते रहे, लेकिन यह लगभग 100 डालर प्रति बैरल के आस–पास चलती रही। तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा के कारण उनकी कमी से तो जनता प्रभावित थी ही, तेल की बढ़ती कीमतों के कारण दुनिया भर में मंहगाई बढ़ती जा रही थी। हालांकि अमरीका स्वयं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, फिर भी तेल की इस मंहगाई से अमरीका भी अछूता नहीं था। इस संदर्भ में भारत समेत दुनिया भर में अब आयातित तेल पर निर्भरता कम करने की बात चल निकली। इसमें पहला सवाल यह था कि क्या ईंधन में आत्मनिर्भरता संभव है? आज भारत की कच्चे तेल हेतु विदेशों पर निर्भरता लगभग 88 प्रतिशत है और अपनी गैस संबंधी आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत हम आयात करते है। हार्मुज का मार्ग अवरोध होने के बाद अचानक इन पदार्थों की किल्लत के कारण न केवल उनकी कीमतों पर असर पड़ा, बल्कि हमारे छोटे–छोटे रेस्टोरेंट और रेहड़ी–पटरी पर चाय बेचने वालों से लेकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जो गैस पर निर्भर थे, उनके व्यवसाय पर असर पड़ना शुरू हो गया। ऐसे में देश में यह विचार शुरू हुआ कि भारत ईंधन और ऊर्जा की दृष्टि से कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने हेतु जो सात आग्रह देश की जनता से किए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम, सीधे–सीधे पेट्रोलियम उत्पादों पर देश की निर्भरता कम करने की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन समझना होगा कि अल्पकाल में तो हम ऊर्जा का कम उपयोग करके विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं लेकिन दीर्घकाल में ऊर्जा आत्मनिर्भरता ही एक मात्र विकल्प है। बायो–गैस पेट्रोलियम गैस का एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है। आज भारत के ऐसे संसाधनों, जिसमें गोबर, कृषि अवशेष, घरेलू कूड़ा इत्यादि कई ऐसे स्रोत है जिनसे बायो गैस बनायी जा सकती है। जिसमें से मात्र 5 प्रतिशत ही उपयोग कर पा रहे है। स्वाभाविक है कि यदि इस संबंध में प्रयास हों तो हर गांव और ग्राम समूह के स्तर पर बायो गैस प्लांट लगाये जा सकते हैं और उनसे न केवल गांवों की स्थानीय ईंधन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, और आयातित गैस पर निर्भरता कम हो सकती है, बल्कि ईंधन की लागत को भी काफ़ी कम किया जा सकता है।

यही नहीं वाहनों में थोड़ा बहुत बदलाव करके हम उन्हें भी बायो गैस पर चला सकते है। देश में पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए अभी भी अपरिहार्य माना जाता रहा है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आज से एक दशक पहले तक भारत में बिजली की कमी हुआ करती थी, लेकिन आज पूरे देश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होने के बाद भी बिजली का अतिरेक रिकार्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पिछले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पदन की क्षमता में भरपूर वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जो 2014 में मात्र 35 गीगावाट की थी, अभी तक बढ़कर 200 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है और इसमें हर साल 25 से 30 गीगावाट क्षमता जुड़ जाती है।

हालांकि पहले भी बढ़ती ऊर्जा कीमतें हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित कर रही थीं, लेकिन युद्ध के कारण कीमतों में और बढ़ोतरी और आपूर्ति में रुकावटों ने इन प्रयासों को और तेज़ कर दिया है। बिजली उत्पादन के लिए बड़ी क्षमता स्थापित करने के परिणामस्वरूप, भारत ऊर्जा क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है; बल्कि हम ऑफ–पीक घंटों के दौरान अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी करते हैं। इसलिए, अब पेट्रोल और डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने का समय आ गया है। हम आसानी से इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक ट्रकों, इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक स्कूटरों को अपना सकते हैं। इससे भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की बचत हो सकती है, और इस प्रकार विदेशों पर निर्भरता कम हो सकती है और कीमती विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। आवागमन के अलावा, हम बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरणों, जैसे इंडक्शन, का भी अधिक उपयोग कर सकते हैं। देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुसंधान में नए विकास हमारी ऊर्जा सुरक्षा को और बढ़ा सकते हैं। सरकार बायो–गैस उत्पादन को बड़ा बढ़ावा दे रही है, और अनुसंधान और विकास भी बायो–गैस को संकुचित (कम्प्रेस) करने में मदद कर रहा है और वाहनों में इसका उपयोग भी संभव हो रहा है। इस तरह के प्रयोग पहले से ही सफल हो रहे हैं।

भारत में पारंपरिक रूप से गाड़ियाँ पेट्रोल, डीज़ल और बाद में सीएनजी से चलती थीं। पिछले कुछ सालों में हाइब्रिड कारों का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जिनमें ईंधन की खपत कम होती थी क्योंकि गाड़ियाँ कुछ हद तक पेट्रोल और कुछ हद तक बैटरी से चलती थीं। हाल के समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हुआ है। ईवी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जून 2026 में स्कूटर सेगमेंट में ईवी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से ज्यादा हो गई, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी कुल कार बिक्री का लगभग 8 प्रतिशत थी, और यह समय के साथ लगातार बढ़ रही है। युद्ध से पहले, जनवरी 2026 में, कुल गाड़ियों की खरीद में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी मुश्किल से 3.6 प्रतिशत थी।

कुल मिलाकर, हम कह सकते हैं कि हालांकि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास पहले से ही चल रहे थे, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और उसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई में व्यवधान ने ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन दिया है। हमें इस प्रक्रिया को धीमे नहीं होने देना चाहिए।

इसरो वैज्ञानिकों के त्यागपत्र

अंतरिक्ष में, निजी क्षेत्र को लाभ

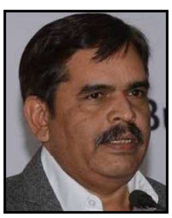

सार्वजनिक प्रतिष्ठान 'इसरो' से वैज्ञानिकों को निजी क्षेत्र में जाना स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जा सकती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि देश के लिए 'गगनयान' जैसे अहम मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिक भी निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, जो 'इसरो' के लिए एक चेतावनी भी है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

कुछ दिन पहले आयी एक खबर, जिसे अत्यंत नकारात्मक तरीके से देखा जा रहा था, यह थी कि भारत के एक गौरवपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने या तो संस्थान से त्यागपत्र दे दिया है अथवा समय से पूर्व सेवानिवृत्ति ले ली है। इस खबर से ऐसा लग रहा था कि शायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को इससे एक बड़ा झटका मिल सकता है। लेकिन वहीं एक निजी कंपनी द्वारा बिना कोई असफलता झेले अंतरिक्ष में अपना रॉकेट लॉन्च करने के बाद यह बात स्पष्ट हो रही है कि 'इसरो' के वैज्ञानिक संस्थान से तो अलग हो रहे हैं, लेकिन वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग नहीं हो रहे, बल्कि एक अन्य प्रकार से अपना जुड़ाव मजबूती से बनाये हुए हैं, और निजी क्षेत्र के माध्यम से देश के लिए सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं।

जुलाई 18, 2026 को भारत की एक निजी अंतरिक्ष स्पेस कंपनी 'स्काईरूट एरोस्पेस' ने सफलतापूर्वक विक्रम–1 नाम के रॉकेट को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। अब भारत, अमरीका, चीन और जापान के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है, जिसकी किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने में सफलता पाई है। विक्रम–1 की सफलता की खास बात यह है कि जहां बाकी देशों की निजी कंपनियों ने एक या एक से अधिक बार असफलता झेलने के बाद सफल लॉन्च कर पायी, स्काईरूट ने यह काम पहले ही प्रयास में कर दिया है।

प्रारंभ में अत्यंत सामान्य शुरूआत से आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार 'इसरो' ने सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित किए, उससे इस क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा की उत्कृष्टता विश्व में स्थापित हुई है। पीएसएलवी, मंगलयान, चंद्रयान और भविष्य में मानव को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी के साथ पूर्णतया स्वदेशी गगनयान मिशन, नैविक (पूर्णतया स्वदेशी नेवीगेशन) और कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, शहरी नियोजन, मौसम पूर्वानुमान, और मत्सयन के लिए विश्व की सबसे बड़ी रिमोट सेंसिंग सेटेलाईट बनाने सहित 'इसरो' की तमाम उपलब्धियों के बाद भारत सरकार द्वारा ही यह सोचा समझा निर्णय लिया गया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। प्रारंभ में जब भारत के पास अंतरिक्ष क्षमता नहीं थी और दुनिया के विकसित देश हमसे कहीं आगे थे, सरकारी मदद के बिना अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ना इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अपनी प्रौद्योगिकी भारत से साझा करने के लिए तैयार नहीं था। सरकारी मदद और हमारे वैज्ञानिकों की सुझबूझ और मेहनत से इसरो ने विभिन्न उपलब्धियों के माध्यम से देश का मस्तक ऊंचा किया। लेकिन अब यह महसूस किया जा रहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यवसायीकरण की अपार संभावनाएं हैं। पूर्व में भी जन संचार, मौसम विज्ञान एवं विभिन्न प्रकार के शोध में इसरो ने काफी काम किया है, लेकिन स्पेस एक्स एक्सिऑम, स्पेस, सेयरा स्पेस, एस्ट्रो कॉल, डी ऑरबिट सहित विश्व की कई निजी कंपनियों ने अपने व्यवसाय का विस्तार करते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया है। यही नहीं इन कंपनियों का पूंजीगत मूल्यांकन उच्च स्तर पर हो रहा है। अकेले ऐलन मस्क की अमरीकी कंपनी 'स्पेस–एक्स' का पूंजीगत मूल्यांकन 1.6 खरब डालर तक पहुंच चुका है, जो भारत की जीडीपी का लगभग 38 प्रतिशत है।

ऐसे में इन बड़ी स्पेस कंपनियों को टक्कर देने हेतु भारत को भी अपनी तैयारी करनी होगी। भारत में 'स्टार्टअप इको सिस्टम' ने पिछले लगभग 12 सालों में खासी तेजी से प्रगति की है, और इसी क्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नए स्टार्टअप उभरे हैं। इन स्टार्टएप्स को बड़ा लाभ यह मिला है कि अपने ही देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में खास उपलब्धियां हासिल किये हुए वैज्ञानिकों का एक बड़ा मंच देश में ही उपलब्ध है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के पास भी नए विकल्प आ रहे हैं, कि वे या तो अपने स्टार्टअप शुरू करें, अथवा नए स्टार्टएप्स के साथ काम करते हुए अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए–नए आयामों को आगे बढ़ाने में मदद दें।

इतिहास से सबक लेने की जरूरत

1960, 1970 व 1980 के दशक में देश की आकांक्षी युवा पीढ़ी ने देश में अवसरों के अभाव में भारत से पलायन करना शुरू कर दिया। यह वह कालखंड था जब देश में समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में देश की सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने के मार्ग अवरूद्ध कर दिये गये। नीति निर्माताओं की सोच यह थी कि देश में निजी क्षेत्र नई प्रौद्योगिकी के साथ उद्यमिता के विकास में सक्षम नहीं है। न तो उसके पास संसाधन है, न तकनीकी क्षमता और न ही जाखिम लेने का रूझान। ऐसे में सरकार ने देश में औद्योगिक विकास को गति देने का समस्त दायित्व स्वयं पर थोप लिया। ब्रेड से लेकर मशीनरी, इलैक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, दवाईयां, रसायन आदि सभी वस्तुओं का उत्पादन सरकार स्वयं करने लगी।

ऐसी परिस्थितियों में देश के आकांक्षी युवा, संसाधनों, अवसरों और सरकारी मदद के अभाव में विदेशों की ओर रूख करने लगे। आज यदि देखें, यूरोप के विभिन्न देशों अमरीका ही नहीं बल्कि खाड़ी के देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीयों ने जाना शुरू कर दिया और इन देशों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूरोप और अमरीका में भारतीयों ने केवल नौकरियां ही प्राप्त नहीं की, बल्कि वहां के उद्यमिता के विकास में भी उनकी महती भूमिका रही। भारतीय वैज्ञानिक अमरीका के अंतरिक्ष संस्थान 'नासा' में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारतीय डॉक्टर और भारतीय अध्यापक, सभी भारत के ब्रांड एंबेसेडर बनकर दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीयों की प्रतिभा का उपयोग भारत में ही पूर्ण रूप से नहीं हो पाया।

आज भारतीय वैज्ञानिकों, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान 'इसरो' के माध्यम से देश की सफलता के झंडे गाड़े, वे अब या तो निजी क्षेत्र की कंपनियां बनाकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं अथवा देश के युवा वैज्ञानिक स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष क्षेत्र में नई–नई गतिविधियों को अंजाम देने लगे हैं। मात्र कुछ ही सालों में जिस प्रकार से अंतरिक्ष के माध्यम से इंटरनेट का विस्तार हुआ है, और वो दिन दूर नहीं जब दूर–दूर के देशों की भी यात्रा अंतरिक्ष के माध्यम से आसान हो जायेगी। दूरसंचार, नेविगेशन ही नहीं बल्कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी अंतरिक्ष क्षेत्र का बड़ा योगदान होने वाला है। ऐसे में विकास के इन तमाम अवसरों को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए छोड़ देना बहुत समझदारी की बात नहीं है। हमारे सभी प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा और अधिक वैज्ञानिक तैयार करने और देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में महाशक्ति बनाने में 'इसरो' के पूर्व वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जैसे–जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को उनके ज्ञान और अनुभव का ज्यादा लाभ मिलने लगेगा, देश के ज्यादा से ज्यादा युवा वैज्ञानिक इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे।

इस प्रकार की सोच केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में लाने की जरूरत है। प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया में एक महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम नई संभावनाएं जन्म ले रही है। रेयर अर्थ मेटेरियल की प्रोसेसिंग और उत्पादन में भी अपार संभावनाएं हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, क्वांटम कम्प्यूटिंग, ई–कॉमर्स समेत विभिन्न क्षेत्र युवाओं के लिए नये अवसर खोल रहे हैं। ऐसे में पेशेवरों की निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में आवाजाही देश के विकास की एक नई कहानी लिख सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र का स्वस्थ विकास भी जरूरी

हालांकि सार्वजनिक प्रतिष्ठान 'इसरो' से वैज्ञानिकों को निजी क्षेत्र में जाना स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जा सकती है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि देश के लिए 'गगनयान' जैसे अहम मिशन पर काम कर रहे वैज्ञानिक भी निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, जो 'इसरो' के लिए एक चेतावनी भी है। जानकारों का मानना है कि नौकरशाही के बेवजह दखल के चलते वैज्ञानिकों की स्वायत्तता बाधित हो रही है। इसलिए जरूरत इस बात ही भी है कि 'इसरो' और स्पेस कमीशन को फिर से अधिकार सौंपे जायें और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उचित मुआवजा भी मिले। स्वायत्तता और उचित मेहनताने से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होगी और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बल मिलेगा। ❑❑

स्वदेशी की ताकत से मिली स्काईरूट को कामयाबी

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक नए और ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की दशकों की उपलब्धियों के बाद देश की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट ने अपने विक्रम–1 रॉकेट से प्रदर्शनात्मक सामग्री पृथ्वी की एक निकट कक्षा में निर्धारित जगह पर पहुंचा दिया है। श्रीहरिकोटा से स्काई रूट एयरोस्पेस का सफल कक्षीय प्रक्षेपण केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की नई शुरुआत का सुनहरा अध्याय भी है। तकनीकी तौर पर देखें तो विक्रम–1 रॉकेट कंपोजिट कार्बन जैसी अपेक्षाकृत हल्की सामग्री से बना हुआ है और इसका लिक्विड फ्यूल इंजन 3–डी प्रिंटिंग से तैयार किया गया है। यह 4 स्टेज रॉकेट है जिसकी तीन स्टेजेज सॉलि़ड फ्यूल से और चौथी यानी आखिरी स्टेज लिक्विड फ्यूल से चलने वाली है। किराए के मामले में यह थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन कोई टीवी कंपनी फटाफट अपना सैटेलाइट चाहती है तो उसे अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। यह मिशन इसलिए भी विशेष है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय निजी कंपनी अपने विकसित किए गए रॉकेट के माध्यम से उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है। 19 जुलाई 2026 को हुए सफल प्रक्षेपण के बाद भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां सरकारी एजेंसियों के साथ–साथ निजी कंपनियां भी स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष प्रक्षेपण करने में सक्षम बन रही हैं।

‘विक्रम–1’ भारत का पहला निजी रूप से स्वदेशी तकनीक पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। यह रॉकेट भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते निजी निवेश, स्वदेशी तकनीक और नवाचार का प्रतीक माना जा रहा है। अब तक इस प्रकार के मिशन का नेतृत्व मुख्य रूप से इसरो करता रहा है लेकिन अब निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय स्टार्टअप द्वारा अर्जित यह सफलता भविष्य में भारत में निजी उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के नए अवसर खोलेगी और वैश्विक

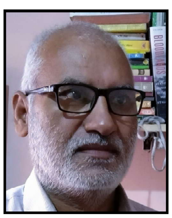

स्वदेशी तकनीक से विकसित यह उड़ान न केवल भारत के वैज्ञानिक सामर्थ को नई ऊंचाई देने वाली है बल्कि दुनिया को यह संदेश भी गया है कि भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र अंतरिक्ष की नई सीमाओं को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

–अनिल तिवारी

वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भागीदारी को भी मजबूत करेगी।

विक्रम–1 छोटे सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला रॉकेट है। इसरो धीरे–धीरे 500 किलो से कम के सेटेलाइट की लांचिंग से दूरी बना रहा है। हालांकि स्काई रूट की रॉकेट सेवा अभी 350 किलो तक के लांचिंग के लिए ही डिजाइन की गई है लेकिन भविष्य में विक्रम रॉकेट के अगले मॉडल 800 किलोग्राम तक के लॉन्च करने की योजना है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब स्काईरूट एरोस्पेस अपना लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे।

पूरी दुनिया में सिर्फ चार देश ऐसे हैं जो स्पेस लॉन्च सेक्टर में निजी उद्यमों के प्रवेश की व्यवस्था कर सके हैं। अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत का नाम शामिल हो गया है। इससे भारत के नवाचार को बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इस क्षेत्र में निजी उद्यमों को बढ़ावा देने का घोषित लक्ष्य यह है कि इसके बल पर सैटेलाइट भेजने का खर्चा इसरो की तुलना में पांचवें हिस्से तक लाया जा सकता है। अभी इस पर 20 से 25 करोड़ का खर्च आने की बात कही गई है जबकि सबसे सस्ती इसरो की लॉन्चिंग 30 से 35 करोड़ में होती है। भारत के वैज्ञानिकों ने सेटेलाइट टेक्नोलॉजी का सुदृढ़ ढांचा खड़ा किया है। इसलिए क्षेत्र में निजी भागीदारों के शामिल होने के बाद बहुस्तरीय नवाचार गुणात्मक गति से आगे बढ़ेगा।

स्पेस एक्स ने अगले कुछ वर्षों में 50000 और चीन ने 12500 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रखी है। इस माहौल में भारत आकाश से लेकर जमीन तक अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के नवाचारों को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। भारत राकेटों के पुनर्प्रयोग के लिए भी तैयारी कर रहा है। जिस तरह अमेरिका और चीन अपने राकेटो को सुरक्षित उतार कर उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लायक बना लेते हैं, स्काई रूट एयरोस्पेस के लिए यह काम ज्यादा आसान है क्योंकि इसका मटेरियल उन देशों की तुलना में बहुत हल्का है। स्काई रूट के वैज्ञानिक रॉकेट कैप्चर टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगे हुए हैं।

पिछले कुछ सालों में भारत में निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वारा खोले हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र जैसी संस्थाओं की स्थापना और नई अंतरिक्ष नीति ने निजी उद्योगों को इस क्षेत्र में निवेश और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया है।

इस मिशन की एक विशेष सांस्कृतिक पहचान भी है। विक्रम–1 अपने साथ एक सूक्ष्म स्वर्ण रॉकेट ले गया जिसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई सर चंद्रशेखर वेंकट रमन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म प्रतिमाएं भेजी गई। यह विज्ञान संस्कृत और भारत की वैज्ञानिक विरासत को एक साथ जोड़ने का अनूठा प्रयास है। 'मिशन आगमन' वंदे मातरम अंकित प्रधानमंत्री का संदेश और दुनिया भर से प्राप्त शुभकामनाओं का संदेश भी ले गया। यह पहला भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को नागरिक आकांक्षाओं से जोड़ने का प्रतीकात्मक प्रयास है।

विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रम–1 की सफलता भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है भारत ने आने वाले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और निजी निवेश के क्षेत्र में यह मिशन मील का पत्थर साबित हो सकता है।

पिछले कुछ सालों में भारत ने निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वारा खोले हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र जैसी संस्थाओं की स्थापना और नई अंतरिक्ष नीति ने निजी उद्योगों को इस क्षेत्र में निवेश और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया है। स्काईरूट एयरोस्पेस की यह उपलब्धि इसी नीति का परिणाम मानी जा रही है। स्वदेशी तकनीक से विकसित यह उड़ान न केवल भारत के वैज्ञानिक सामर्थ को नई ऊंचाई देने वाली है बल्कि दुनिया को यह संदेश भी गया है कि भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र अंतरिक्ष की नई सीमाओं को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ❑❑

देशी, स्वदेशी और विदेशी

नदिया-पूर्व बर्दवान के ताँत उद्योग के आलोक में भारतीय आर्थिक चिंतन का एक तात्त्विक विवेचन

नवद्वीप (पश्चिम बंगाल) की एक संकरी गली में एक वृद्ध बुनकर अपने करघे पर बैठा था। उसके हाथ धागे बुन रहे थे, पर वास्तव में वह केवल एक साड़ी नहीं बुन रहा था – वह अपने परिवार की आजीविका, अपने गाँव की अर्थव्यवस्था और भारत की एक जीवंत आर्थिक परंपरा को जीवित रखे हुए था। "हम केवल साड़ी नहीं बुनते; अपने परिवार और अपने गाँव का भविष्य भी बुनते हैं," उसने कहा। इसी एक वाक्य ने इस लेख को जन्म दिया।

हाल ही में मुझे नदिया तथा पूर्व बर्दवान के कुछ ताँत बुनकरों (ताँतियों) के बीच जाने, उनसे संवाद करने और उनकी जीविका की वास्तविक स्थिति को निकट से समझने का अवसर मिला। श्रीरामपुर, नवद्वीप धाम तथा आसपास के अनेक गाँवों में हाथ से बुनी हुई सूती ताँत साड़ियों के निर्माण और व्यापार से जुड़े परिवारों से मिलकर यह स्पष्ट हुआ कि यह केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक जीवंत सांस्कृतिक और आर्थिक परंपरा है।

इन दोनों जिलों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाखों लोग ताँत उद्योग से जुड़े हैं – बुनकर, सूत व्यापारी, रंगाई करने वाले, डिज़ाइनर, फिनिशिंग और पैकिंग करने वाले, परिवहनकर्ता तथा छोटे व्यापारी। यह पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था आज गहरे संकट से गुजर रही है। अनेक बुनकर अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, और नई पीढ़ी इस परंपरा में अपना भविष्य नहीं देख रही है।

इस संकट का मूल कारण केवल बाज़ार की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि तीन भिन्न प्रकार की वस्तुओं का एक साथ बाज़ार में उपस्थित होना है – देशी, स्वदेशी और विदेशी। यह

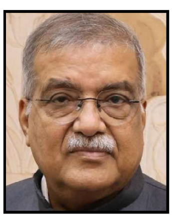

आज भारत "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" की बात कर रहा है। इन अभियानों की सफलता तभी संभव है जब "लोकल" का अर्थ केवल नारा न रह जाए, बल्कि आर्थिक नीति का ठोस आधार बने।

– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

श्रेणी	अर्थ	उदाहरण
देशी	स्थानीय समुदाय द्वारा, स्थानीय संसाधनों व कौशल से निर्मित	नवद्वीप, शांतिपुर, फुलिया की ताँत साड़ी
स्वदेशी	भारत के अन्य भागों में निर्मित	सूरत की पावरलूम साड़ी
विदेशी	भारत के बाहर, आयातित	बांग्लादेश की हैंडलूम व पावरलूम साड़ियाँ

भेद यदि केवल भावनात्मक अपील न रहकर एक आर्थिक सिद्धांत के रूप में समझा जाए, तो यह स्वदेशी चिंतन में एक नया आयाम जोड़ सकता है।

देशी, स्वदेशी और विदेशीः तीनों में मूलभूत अंतर

देशी का अर्थ केवल भारत में बनी वस्तु नहीं है। देशी वह है – जो किसी क्षेत्र की स्थानीय प्रकृति, संस्कृति, कौशल, संसाधन और समाज की आर्थिक संरचना से जन्म लेती है। नवद्वीप, शांतिपुर, फुलिया या पूर्व बर्दवान की ताँत साड़ी इसलिए देशी है क्योंकि उसका निर्माण वहीं के लोगों द्वारा, वहीं के कौशल के आधार पर होता है, और उसकी आय पुनः उसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होती है। देशी का केंद्र केवल वस्तु नहीं, स्थानीय समाज है।

स्वदेशी का अर्थ है – अपने राष्ट्र में निर्मित वस्तु का सम्मान और उपयोग। सूरत की पावरलूम साड़ियाँ स्वदेशी हैं क्योंकि उनका निर्माण भारत में होता है और वे भारतीय उद्योग व रोज़गार का सृजन करती हैं।

विदेशी वह है – जिसके उत्पादन से उत्पन्न रोज़गार, आय और मूल्य–संवर्धन भारत के बाहर जाता है, जैसे बांग्लादेश से आने वाली हैंडलूम व पावरलूम साड़ियाँ। जब उपभोक्ता विदेशी वस्तु खरीदता है, तो उसका धन स्थानीय अर्थव्यवस्था से निकलकर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है।

यह वर्गीकरण केवल भौगोलिक नहीं है; इसका सीधा संबंध रोज़गार, आय, पूँजी के प्रवाह और सामाजिक स्थिरता से है।

आर्थिक कोरः स्थानीय गुणक प्रभाव

यदि कोई उपभोक्ता नवद्वीप की एक ताँत साड़ी खरीदता है, तो उसका मूल्य सूत विक्रेता, रंगाई करने वाले, बुनकर, डिज़ाइनर, स्थानीय व्यापारी और परिवहनकर्ता – इन सबके बीच बँटता है। अर्थात एक ही गाँव में आय का बहुगुणक प्रभाव (लोकल मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट) उत्पन्न होता है – एक रुपया कई बार उसी स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमकर मूल्य बढ़ाता है।

इसके विपरीत, यदि वही उपभोक्ता सूरत की मशीन–निर्मित साड़ी खरीदता है, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ अवश्य होता है, परन्तु नवद्वीप का स्थानीय आर्थिक चक्र रुक जाता है। यहीं एक सूक्ष्म किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि सूरत की अत्यधिक यंत्रीकृत, कम लागत वाली पावरलूम साड़ियाँ नदिया और पूर्व बर्दवान के परम्परागत बाज़ार पर अधिकार कर लें, तो राष्ट्र के भीतर ही एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र की आजीविका को समाप्त करने लगता है।

अतः स्वदेशी का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संतुलन बनाए रखना भी है। यदि राष्ट्रीय उत्पादन स्थानीय जीवन को नष्ट करने लगे, तो स्वदेशी की आत्मा अधूरी रह जाती है।

और यदि वही उपभोक्ता बांग्लादेश की साड़ी खरीदता है, तो भारतीय रोज़गार नहीं बढ़ता, भारतीय उत्पादन नहीं बढ़ता, विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, और स्थानीय उद्योग और अधिक कमज़ोर होता है – इसीलिए लगभग सभी विकसित देश अपने पारम्परिक उद्योगों की किसी न किसी रूप में रक्षा करते हैं।

आर्थिक त्रिकुटीः तीन प्रकार की प्रतिस्पर्धा

- *देशी (स्थानीय ताँत)* – श्रमप्रधान, सांस्कृतिक, सीमित उत्पादन, उच्च कौशल
- *स्वदेशी (सूरत पावरलूम)* – यंत्रीकृत, कम लागत, बड़े पैमाने का उत्पादन
- *विदेशी (बांग्लादेशी साड़ियाँ)* –

आयातित, मूल्य–प्रतिस्पर्धी, स्थानीय बाज़ार पर दबाव

पहली प्रतिस्पर्धा स्थानीय कौशल और मशीन के बीच है। दूसरी प्रतिस्पर्धा भारत के दो आर्थिक मॉडलों के बीच है। तीसरी प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय और विदेशी अर्थव्यवस्था के बीच है। यदि केवल मूल्य (प्राइस) को निर्णायक आधार बनाया जाए, तो मशीन सदैव हस्तकला पर भारी पड़ेगी – परन्तु यदि रोज़गार, संस्कृति और सामाजिक पूँजी को भी आर्थिक मूल्य माना जाए, तो निर्णय बदल जाता है।

विश्व के उदाहरणः यह केवल भारत की समस्या नहीं

जापान ने आधुनिक औद्योगीकरण के बावजूद अपने पारम्परिक किमोनो उद्योग को संरक्षण दिया; मशीन–निर्मित वस्त्रों के युग में भी हस्तनिर्मित किमोनो आज सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं। इटली का टस्कनी लेदर, मुरानो ग्लास और हस्तनिर्मित फैशन उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बावजूद इसलिए जीवित है क्योंकि वहाँ सरकार, उपभोक्ता और बाज़ार स्थानीय शिल्प को विशेष पहचान देते हैं। फ्रांस में स्थानीय पनीर, वाइन और हस्तशिल्प को ''प्रोटेक्टेड डिजिगनेशन ऑफ ओरिजिन (पीडीओ)'' जैसी कानूनी सुरक्षा प्राप्त है – ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि विकसित राष्ट्र भी अपनी स्थानीय पारम्परिक अर्थव्यवस्था को सायास संरक्षित करते हैं।

भारत के लिए शिक्षा

भारत में भी बनारसी साड़ी, कांचीपुरम सिल्क, चंदेरी, महेश्वरी, भागलपुरी, बालूचरी और बंगाल ताँत जैसी अनेक परम्पराएँ इसी चुनौती का सामना कर रही हैं। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि ताँत उद्योग कोई सीमांत क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है –

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र एवं परिधान उत्पादक देश है, और यह क्षेत्र देश के सबसे बड़े रोज़गार–प्रदाताओं में से एक है।
- भारत सरकार की चौथी अखिल भारतीय हथकरघा गणना (2019–20) के अनुसार लगभग 35 लाख से अधिक बुनकर व संबद्ध कार्यकर्ता हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हैं।
- भारत में 600 से अधिक हस्तकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) का दर्जा प्राप्त है, जिनमें शांतिपुर साड़ी और फुलिया ताँत भी सम्मिलित हैं, इसका उद्देश्य स्थानीय परंपरा और उत्पाद की विशिष्ट पहचान की रक्षा करना है।

तात्त्विक आधारः दीनदयाल उपाध्याय और गांधीजी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट कहा था कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल उत्पादन नहीं, बल्कि मनुष्य का समग्र विकास है। उन्होंने "अर्थायाम" की अवधारणा में अर्थ को धर्म, समाज और संस्कृति से जोड़कर देखा, और यह माना कि ऐसी अर्थव्यवस्था उचित नहीं हो सकती जिसमें उत्पादन तो बढ़े किन्तु बेरोज़गारी भी बढ़ती जाए। नदिया का ताँत उद्योग ठीक इसी प्रश्न को हमारे सामने रखता है।

महात्मा गांधी ने लिखा था कि स्वदेशी का अर्थ है – अपने निकटवर्ती पड़ोसी की सेवा करना। गांधीजी ने कभी केवल भारतीय वस्तु खरीदने की बात नहीं कही – उन्होंने पहले अपने गाँव, फिर अपने क्षेत्र, और उसके बाद अपने राष्ट्र की सेवा की बात की। यही देशी और स्वदेशी के बीच का वास्तविक सम्बन्ध हैः स्वदेशी, देशी से होकर ही परिपूर्ण होता है।

यदि कोई वस्तु सस्ती है, परन्तु उससे लाखों परिवार बेरोज़गार हो जाते हैं, तो उसका मूल्य केवल रुपये में नहीं आँका जा सकता। यदि किसी उत्पाद के कारण किसी क्षेत्र की शताब्दियों पुरानी कला समाप्त हो जाती है, तो वह केवल आर्थिक हानि नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पूँजी का विनाश है।

एक नया आर्थिक सिद्धान्तः प्राथमिकता–क्रम

विदेशी वस्तु राष्ट्रीय संपदा को बाहर ले जाती है। स्वदेशी वस्तु राष्ट्रीय संपदा को देश में रखती है। देशी वस्तु स्थानीय समाज की संपदा, संस्कृति और रोज़गार को जीवित रखती है। इसीलिए आर्थिक नीति का क्रम होना चाहिए –

- पहली प्राथमिकता – देशी
- दूसरी प्राथमिकता – स्वदेशी
- तीसरी और अंतिम – विदेशी

स्वदेशी का वास्तविक अर्थ केवल

"भारतीय वस्तु खरीदो" का नारा नहीं है। स्वदेशी का अर्थ है – उत्पादन का विकेंद्रीकरण, स्थानीय कौशल का संरक्षण, अधिकतम रोज़गार–सृजन, आत्मनिर्भर समुदायों का निर्माण, और अर्थव्यवस्था को मानव–केंद्रित बनाना।

नीतिगत समाधान

तॉंत उद्योग को केवल अनुदान देकर जीवित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए एक समग्र रणनीति आवश्यक है –

- स्थानीय तॉंत को विशिष्ट भौगोलिक पहचान (जीआई ब्रांड) के रूप में विकसित किया जाए।
- डिज़ाइन, विपणन और ई–कॉमर्स से जोड़ा जाए।
- सरकारी खरीद में स्थानीय तॉंत को प्राथमिकता मिले।
- विदेशी साड़ियों के अनुचित आयात पर प्रभावी निगरानी हो।
- उपभोक्ताओं में "स्थानीय खरीदें, स्थानीय बचाएँ" का जन–अभियान चलाया जाए।
- प्रत्येक जिले की अपनी पारंपरिक–उद्योग नीति तैयार की जाए।

विस्तृत दृष्टिः "देशी अर्थव्यवस्था" – 21वीं सदी का नया आर्थिक प्रतिमान

नवद्वीप का यह अनुभव एक व्यापक प्रश्न की ओर ले जाता है। इक्कीसवीं सदी का विश्व केवल राजनीतिक परिवर्तन का नहीं, बल्कि आर्थिक प्रतिमानों के पुनर्निर्माण का भी साक्षी बन रहा है। कोविड–19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता उजागर की, व्यापार–युद्धों ने मुक्त व्यापार की सीमाएँ स्पष्ट कीं, और आज विश्व का मूल प्रश्न केवल यह नहीं कि अधिक उत्पादन कैसे हो, बल्कि यह कि विकास ऐसा कैसे हो जो मानव, समाज, प्रकृति और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

इसी संदर्भ में मैं "देशी अर्थव्यवस्था" की अवधारणा प्रस्तुत करना चाहता हूँ – यहाँ "देशी" कोई संकीर्ण भावनात्मक आग्रह नहीं, बल्कि स्थानीय आर्थिक पारिस्थितिकी पर आधारित एक आर्थिक सिद्धांत है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन, मानवीय कौशल, स्थानीय पूँजी, उद्यमशीलता, सामाजिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपरा मिलकर जो आत्मपोषित आर्थिक तंत्र निर्मित करते हैं, वही देशी अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत को यदि समझना है, तो केवल उसके जीडीपी को नहीं, बल्कि उसके जिलों, कस्बों और गाँवों की आर्थिक जीवंतता को समझना होगा।

> **यदि प्रत्येक भारतीय वर्ष में केवल एक स्थानीय हथकरघा उत्पाद खरीदने का संकल्प ले, तो लाखों बुनकर परिवारों की आजीविका सुरक्षित हो सकती है - यही देशी से स्वदेशी, और स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक यात्रा है।**

नवद्वीप का तॉंत उद्योग, मुरादाबाद का पीतल, भदोही के कालीन, कन्नौज का इत्र, कच्छ की कढ़ाई, सूरत का वस्त्र उद्योग, तिरुपुर का निटवेयर, कोयम्बटूर की इंजीनियरिंग – ये केवल उद्योग नहीं, स्थानीय आर्थिक पारिस्थितिकियों के जीवंत उदाहरण हैं, जिनमें कच्चे माल से लेकर कौशल, वित्त, परिवहन और सामाजिक संबंधों की पूरी श्रृंखला सक्रिय रहती है।

यह प्रतिमान न तो संरक्षणवाद है, न वैश्वीकरण का विरोध। यह कहता है कि विश्व के साथ वही राष्ट्र सम्मानपूर्वक खड़ा हो सकता है जिसकी स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। इसीलिए विकासक्रम यह होना चाहिए – स्थानीय समृद्धि – राष्ट्रीय शक्ति – वैश्विक नेतृत्व, अर्थात देशी – स्वदेशी – वैश्विक सहभागिता।

निष्कर्ष

नदिया और पूर्व बर्दवान का तॉंत उद्योग हमें एक गहरा आर्थिक सत्य सिखाता है – हर स्वदेशी वस्तु देशी नहीं होती, और हर देशी वस्तु का संरक्षण स्वदेशी की आत्मा का अनिवार्य अंग है। विदेशी वस्तुओं की चुनौती स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु राष्ट्रीय स्तर की यंत्रीकृत प्रतिस्पर्धा भी कभी–कभी स्थानीय अर्थव्यवस्था को उतना ही आहत कर सकती है।

अतः आर्थिक नीति का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि उत्पादन, रोज़गार, संस्कृति और क्षेत्रीय संतुलन – इन चारों का समन्वय होना चाहिए। स्वदेशी का वास्तविक संदेश यही है कि जिस अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यक्ति की आजीविका सुरक्षित रहती है, वही राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि का आधार बनती है। स्थानीय उत्पादन का संरक्षण किसी प्रकार का संरक्षणवाद नहीं, बल्कि भारत की बहुरंगी आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता और करोड़ों परिवारों की गरिमामय आजीविका की रक्षा का एक राष्ट्रीय दायित्व है।

आज भारत "वोकल फॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" की बात कर रहा है। इन अभियानों की सफलता तभी संभव है जब "लोकल" का अर्थ केवल नारा न रह जाए, बल्कि आर्थिक नीति का ठोस आधार बने। यदि प्रत्येक भारतीय वर्ष में केवल एक स्थानीय हथकरघा उत्पाद खरीदने का संकल्प ले, तो लाखों बुनकर परिवारों की आजीविका सुरक्षित हो सकती है – यही देशी से स्वदेशी, और स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक यात्रा है। ❑❑

(लेखक, प्रधान शोधकर्ता और संस्थापक निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड (आईआईट्रेड), कोलकाता है।)

गांवों में भी बढ़ी 'फोटो-एल्बम' की जगह 'रील्स' की मांग

डिजिटल कंटेंट क्रिएशन आज युवाओं के लिए तेजी से उभरता हुआ कैरियर बन चुका है। फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग, म्यूजिक फोटोग्राफी, शिक्षा, खेती बागवानी और वीडियो प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान और रोजगार दोनों में बदल रहे हैं।

– शिवनंदन लाल

ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन रोजगार और स्वरोजगार का एक बेहतरीन माध्यम बन रहा है। ग्रामीण युवा अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके कृषि, बागवानी, स्थानीय संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन, खान–पान, वेशभूषा, रहन–सहन जैसे विषयों पर वीडियो रील्स और ब्लॉग बनाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज ढेर सारे युवा डिजिटल क्रिएशन के जरिए अपनी पहचान बन चुके हैं और स्वरोजगार के मार्फत आय बढ़ाने में सक्षम हुए हैं तथा अन्य युवाओं को भी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अनेक युवा अपनी रुचि के हिसाब से कृषि, बागवानी, स्थानीय कला और संस्कृति, शिक्षा, गांव का जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य जैसे विषय पर रोचक कंटेंट तैयार कर लोगों में जागरूकता तो ला ही रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं तथा इस काम से खुद की आय बढ़ाकर अपने जीवन स्तर में भी सुधार कर रहे हैं।

आज से ठीक 11 साल पहले वर्ष 2015 में भारत ने 'डिजिटल इंडिया मिशन' की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना था। इस मिशन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर एक 1050 मिलियन हो गई है। डिजिटल इंडिया एक सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर एक जन आंदोलन में बदल गया है जिसने पूरे देश में शासन, वाणिज्य, दैनिक जीवन तथा रोजगार प्राप्त करने के अवसरों को मौलिक रूप से बदल दिया है।

ग्रामीण युवाओं के बीच डिजिटल कंटेंट क्रिएटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'इंडिया एआई मिशन' के तहत मुफ्त में कई प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त युवाओं को एआई और आधुनिक तकनीकी स्किल में प्रशिक्षित करने के लिए कई राष्ट्रीय कौशल पहलों और डिजिटल कैंपेन की भी शुरुआत की गई है।

डिजिटलीकरण से ग्रामीण भारत में जबरदस्त बदलाव हो रहा है। अधिक से अधिक युवा प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं और डिजिटल दुनिया से जुड़ रहे हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और अधिक से अधिक ग्रामीण युवा अपने दिनचर्या में डिजिटल उपकरणों को अपना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 24 वर्ष के 94 प्रतिशत युवाओं के पास मोबाइल फोन की सुविधा है हालांकि शहरी क्षेत्र में यह सुविधा 97 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 24 वर्ष के 90 प्रतिशत युवाओं के पास अब इंटरनेट कनेक्शन है जो दर्शाता है कि यह पीढ़ी तेजी से जुड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में ईमेल और इंटरनेट बैंकिंग की भी लोकप्रियता बढ़ी है। डिजिटल कौशल को लगातार अपनाने से ग्रामीण भारत और अधिक सशक्त हो रहा है तथा प्रौद्योगिकी के नए–नए अवसर विकसित होने की संभावना बढ़ी है। सरकार ने भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का निर्माण किया है। डिजिटल इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप और नवाचार योजनाओं को लागू किया है जिसमें टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट आफ एंटरपेन्योर्स, जेन नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर इन्नोवेटिव स्टार्टअप डोमेन, स्पेसिफिक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस और नेक्स्ट जेनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम जैसी योजनाएं शामिल है। इसके अलावा 'भारत नेट परियोजना' भी महत्वपूर्ण है जो

ग्रामीण क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर लाइनों से जोड़ती है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड योजना दूर दराज के समुदायों को 4जी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसे इंटरनेट उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपनाया गया है। भारत बीपीओ प्रमोशन स्कीम और नार्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम कम सेवा वाले क्षेत्रों में आईटी और आईटीइएस विकास को प्रोत्साहित करती है जिसके परिणाम स्वरुप नौकरी की संभावनाएं बढी है। 'पीएम वाणी' कार्यक्रम भी चल रहा है जिसका उद्देश्य से पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करना है। इन सभी परियोजनाओं ने मिलकर डिजिटल संभावनाओं को बढ़ाया है तथा भारत की डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारने में अपेक्षित मदद की है।

आज आए दिन अनेक ऐसे युवाओं की कहानी सामने आती है जो केवल एक मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर व्यापक पहुंच के जरिए हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रतिक्षण नए–नए आइडिया पर काम हो रहा है। जीवन के छोटे–बड़े हर अवसरों की नवीन प्रस्तुति लोगों को लुभा भी रही है। भारतीय वेडिंग इंडस्ट्री में तकनीक और संवेदनाओं के संगम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। अब शादी के रस्मों के साथ–साथ भावनाओं और अनकहे पलों को सहेजने के लिए वेडिंग कंटेंट क्रिएटर की मांग बढ़ी है। यह डिजिटल बदलाव गांव के लिए एक नए अवसर के रूप में आया है, और गांव के युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक नया और मजबूत जरिया बन रहा है।

गांव देहात की शादियों में भी पारंपरिक फोटोग्राफर के साथ–साथ वेडिंग कंटेंट क्रिएटर और वेडिंग सोशल मीडिया मैनेजर की मांग बढ़ रही है। इनका मुख्य काम शादी की रस्मों के साथ–साथ मां की ममता, पिता का मौन और परदे के पीछे के उन अनकहे जज्बातों को सहेजना है जो अक्सर बड़े कैमरों की नजर से छूट जाते हैं।

इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब सर्च और अन्य वीडियो प्लेटफार्म के तेजी से बिस्तार ने नई पीढ़ी की सोच को बदल दिया है। आज युवा अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को हफ्तों बाद नहीं बल्कि उसी रियल टाइम में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर शादी की अपनी एक अनोखी कहानी होती है, कंटेंट क्रिएटर कैमरे के जरिए सिर्फ चेहरों को नहीं बल्कि रिश्तों की धड़कन और भावनाओं को रिकॉर्ड करते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आलम यह है कि अब गांव में भी एल्बम कब मिलेगा की जगह पहला सवाल यह होता है की रील्स कब आएगी? पूछा जाने लगा है।

इस डिजिटल बदलाव के कारण छोटे कस्बों गांवों और ग्रामीण अंचल के रचनात्मक युवाओं के लिए स्वरोजगार और करियर का एक शानदार नया विकल्प बनकर उभरा है।

भारत का ग्रामीण डिजिटल विकास युवाओं को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सशक्त बना रहा है, जिससे दैनिक जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। डिजिटल क्रांति के कारण गांव और शहर के विभाजन कम हो रहे हैं। कम लागत वाले हाई स्पीड इंटरनेट और विभिन्न सरकारी पहलुओं की उपलब्धता के साथ ग्रामीण युवा संचार, स्टार्टअप, शिक्षा, पर्यटन, कृषि बागवानी और आर्थिक विकास के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बन रहे हैं। यह प्रवृत्ति विकास और अवसर को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की बढ़ती समझ को दर्शाती है। जैसे–जैसे डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है, ग्रामीण युवा देश की भविष्य की कनेक्टिविटी और समावेशिता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं।

कुल मिलाकर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन आज युवाओं के लिए तेजी से उभरता हुआ कैरियर बन चुका है। फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग, म्यूजिक फोटोग्राफी, शिक्षा, खेती बागवानी और वीडियो प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पहचान और रोजगार दोनों में बदल रहे हैं। छोटे–छोटे गांव और पहाड़ी इलाकों के क्रिएटर भी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। हाल के दिनों में स्वदेशी जागरण मंच के एसबीए मीडिया प्लेटफार्म से प्रसासित अनेक युवाओं के सफलता की कहानी यह बताती है कि आज रचनात्मकता सिर्फ शौक नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक अवसर बन चुकी है। ❑❑

बूढ़ी होती दुनिया, सिकुड़ते देश, और भारत की चुनौती

साल 2026 का आधा बीतते–बीतते दुनिया की आबादी 8.2 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी है। हर छह हफ्ते में हम न्यूयॉर्क शहर के बराबर आबादी जोड़ रहे हैं। फिर भी, इतिहास में पहली बार, 14वीं सदी के ब्लैक डेथ के बाद से, लगभग हर महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार एक साथ धीमी हो रही है। 20वीं सदी 'अधिक लोगों' की सदी थी, लेकिन 21वीं सदी 'कौन' और 'कहाँ' की सदी होगी। दुनिया एक मौन, परंतु गहरे बदलाव के दौर से गुजर रही है, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की बुनियाद को हिला सकता है।

1975 और 2011 के बीच, दुनिया हर 12 साल में एक अरब लोग जोड़ती थी। यह दौर अब खत्म हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की 'विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024' रिपोर्ट के अनुसार, मानवता 2080 के दशक के मध्य में 10.3 अरब पर चरम पर पहुंचेगी और फिर धीरे–धीरे घटने लगेगी। पहले से ही 60 से अधिक देश हर साल सिकुड़ रहे हैं। चीन ने 2024 में 2 मिलियन लोग खो दिए और 2100 तक उसकी आबादी आधी हो सकती है। जापान 2010 से सिकुड़ रहा है, और आज वहाँ बेबी डायपर से ज्यादा एडल्ट डायपर (बुजुर्गों के लिए) बिकते हैं। इटली में पिछले साल 1861 के बाद पहली बार 4 लाख से कम बच्चे पैदा हुए। बुल्गारिया ने 1989 के बाद से अपनी 22 प्रतिशत आबादी खो दी है।

भारत के लिए, यह समय सबसे नाजुक है। हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन हमारी उम्र भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' है, लेकिन अगर हमने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं किया, तो यह 'डेमोग्राफिक डिजास्टर' बन सकता है।

– प्रो. दीपक शर्मा

इस गिरावट का मुख्य कारण 'प्रजनन दर' (फर्टिलिटी रेट) में कमी है। 1950 में वैश्विक औसत प्रजनन दर 5 बच्चे प्रति महिला थी, जो अब घटकर 2.25 रह गई है। दुनिया के दो–तिहाई देश अब 2.1 की 'प्रतिस्थापन दर' (रिपलेशमेंट रेट) से नीचे हैं, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। यूरोप में यह दर 1.5 है, पूर्वी एशिया में 1.2, और लैटिन अमेरिका में भी यह घटकर 1.8 हो गई है। यह वैश्विक नक्शा दो भागों में बंट रहा है। जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि रुक रही है, वहीं उप–सहारा अफ्रीका 2050 तक 1 अरब लोग जोड़ेगा, जो कुल वैश्विक वृद्धि का आधा से अधिक है। नाइजीरिया की आबादी 375

मिलियन तक पहुँचकर अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। तंजानिया, इथियोपिया और कांगो में 60–80 मिलियन की वृद्धि होगी।

भारतः जनसांख्यिकीय धुरी

भारत इस वैश्विक बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण और केंद्र बिंदु है। 1.46 अरब की आबादी के साथ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बना हुआ है और सिर्फ 'मोमेंटम' (जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार) के कारण हर साल 1 करोड़ लोग जोड़ रहा है। 2021 से भारत की कुल प्रजनन दर 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन दर से नीचे है। केरल में यह दर 1.5 है, जबकि बिहार में 3.0 बनी हुई है, यह उत्तर–दक्षिण का बड़ा विभाजन दिखाता है।

भारत में औसत आयु 29 वर्ष है, जो इसे लगभग 15 साल की 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (डिमोग्राफिक डिविडेंट) की खिड़की देती है। लेकिन देश में पहले से ही 15.3 करोड़ लोग 65 वर्ष से अधिक हैं, जो 2050 तक 34.7 करोड़ हो जाएंगे, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बुजुर्ग समूह होगा। शहरीकरण एक और बड़ी चुनौती है। केवल 36 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है, लेकिन 2050 तक भारत को 41.6 करोड़ और शहरी निवासियों को समायोजित करना होगा, जो इतिहास का सबसे बड़ा शहरी विस्तार होगा।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्नातकों में बेरोजगारी दर 45 प्रतिशत है। अगर भारत को हर साल 1.2 करोड़ नए गैर–कृषि रोजगार सृजित करने होंगे, एक नया पेंशन स्तंभ बनाना होगा, और 25 वर्षों में एक नया 'शहरी फ्रांस' बसाना होगा, तो जनसांख्यिकीय लाभांश 'आपदा' में बदल सकता है। वहीं, भारतीय प्रवासी 2024 में 129 अरब डॉलर का प्रेषण (रेमिटेंस) भेजकर दुनिया में सबसे आगे हैं।

भारत में औसत आयु 29 वर्ष है, जो इसे लगभग 15 साल की 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (डिमोग्राफिक डिविडेंट) की खिड़की देती है।

बूढ़ी होती दुनिया और 'सिल्वर इकोनॉमी'

हम सिर्फ लोग नहीं जोड़ रहे, बल्कि बूढ़े लोग जोड़ रहे हैं। 2026 में मानवता का 10 प्रतिशत 65 वर्ष से अधिक का है। 2050 तक यह 16 प्रतिशत हो जाएगा। 80 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या तीन गुना बढ़कर 45.9 करोड़ हो जाएगी। जापान इसका पूर्वावलोकन हैः वहाँ 30 प्रतिशत नागरिक 65 से अधिक हैं, और 15 प्रतिशत घर खाली हैं। इटली में औसत आयु 48 वर्ष है। चीन में 'एक बच्चा नीति' और बढ़ती उम्र का मतलब है कि 60+ आबादी 2050 तक 29.7 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ हो जाएगी। पारंपरिक कन्फ्यूशियस मॉडल, जहाँ बेटे माता–पिता की देखभाल करते थे, टूट रहा है क्योंकि अब एक बच्चे के लिए दो माता–पिता और चार दादा–दादी हैं।

प्रवासनः एकमात्र उपाय?

जब जन्म दर गिरती है, तो प्रवासन ही जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण बन जाता है। ओईसीडी के 38 देशों में से 27 में यही स्थिति है। कनाडा ने 2023 में 13 लाख लोग जोड़े, जिसमें 98 प्रतिशत प्रवासन से थे। जर्मनी बिना नए आप्रवासियों के 50 साल तक सिकुड़ता रहता। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके सभी विकास के लिए प्रवासन पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 28.1 करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रवासी हैं, जो 2000 में 17.3 करोड़ थे। प्रेषण (रेमिटेंस) 2024 में 860 अरब डॉलर तक पहुँच गए। जलवायु परिवर्तन इसका अगला बड़ा कारण बनेगा। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक जल तनाव, फसल विफलता और समुद्र–स्तर वृद्धि के कारण 21.6 करोड़ लोग अपने ही देशों में विस्थापित हो सकते हैं। बांग्लादेश, वियतनाम और साहेल क्षेत्र शुरुआती हॉटस्पॉट हैं।

निष्कर्ष

200 वर्षों तक, श्अधिक लोगोंश का मतलब 'अधिक शक्ति' था। यह संबंध अब टूट रहा है। नए सवाल हैं कि बूढ़ों की देखभाल कौन करेगा? कर कौन चुकाएगा? फैक्ट्रियों और अस्पतालों में कौन काम करेगा? जनसांख्यिकी भाग्य नहीं है, लेकिन यह सीमाएँ निर्धारित करती है। जो देश पारिवारिक नीति, आप्रवासन, बुजुर्ग देखभाल और शहरी नियोजन को फिर से डिजाइन करेंगे, वे फलेंगे–फूलेंगे। जो आंकड़ों से लड़ेंगे, वे बूढ़े, सिकुड़े हुए और प्रभावहीन हो जाएंगे। विश्व का रंगमंच फिर से बन रहा है। दर्शक बदल रहे हैं, और कुछ सीटें जल्द ही खाली हो जाएंगी।

भारत के लिए, यह समय सबसे नाजुक है। हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन हमारी उम्र भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' है, लेकिन अगर हमने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं किया, तो यह 'डेमोग्राफिक डिजास्टर' बन सकता है। हमें 25 सालों में एक 'नया फ्रांस' बसाना है, 12 करोड़ नौकरियां बनानी हैं, और अपने बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था करनी है। दुनिया बदल रही है, और भारत को इस बदलाव को न केवल स्वीकार करना होगा, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदलना होगा। ❑❑

क्वांटो क्रॉस-करेंसी डेरिवेटिव

पश्चिम एशिया में अमेरिका एवं ईरान तथा इस्राइल एवं लेबनॉन के मध्य युद्ध के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति में अवरोध और होर्मुज जलडमरुमध्य में अमेरिकी और ईरानी वर्चस्व के कारण तेल के जहाजों का मार्ग बार बार बंद होने के कारण सम्पूर्ण विश्व में तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के चलते रुपये की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष विश्व की लगभग सभी मुद्राओं में गिरावट के संकेत है। इसके कारण हमारे आयात महंगे हुए और निर्यात में कमी आई। विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाज़ार और सेक्योरिटीज में भारी बिकवाली की और अपना निवेश कम किया है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि वैश्विक मुद्राओं की अस्थिरता का विपरीत प्रभाव हमारे आयातकों, निर्यातकों और निवेशकों पर कम से कम पड़े। इसी दिशा में नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज की ओर से सकारात्मक पहल की गयी है।

भारतीय एक्सचेंजों पर 'क्वांटो क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव' जैसी योजनाएं लाने से निवेशकों को विनियमित घरेलू मंचों के माध्यम से वैश्विक मुद्राओं का व्यापार करने का अवसर मिलेगा। साथ ही इससे भारतीय मुद्रा के साथ एक विदेशी मुद्रा की जोड़ी के अलावा दूसरे अनुबंधों का क्षेत्र बढ़ाकर एक्सचेंज–ट्रेडेड करेंसी (करेंसी डेरिवेटिव) व्यापार पुनः बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

– विनोद जौहरी

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज घरेलू मुद्रा बाजार में आद्यतन बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक से 'क्वांटो क्रॉस–करेंसी डेरिवेटिव्स' लॉन्च करने की स्वीकृति मांग रहा है। एनएसई के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के स्रोतों से यह जानकारी हुई है। एनएसई को यह नया उत्पाद लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि घरेलू करेंसी डेरिवेटिव्स बाज़ार में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत तेजी से गिरा है। मार्च 2024 में जहां एनएसई पर यह वॉल्यूम 33,165 करोड़ रुपया था, वहीं जून 2026 तक यह घटकर मात्र 5,000 करोड़ रुपया के रह गया। इस भारी गिरावट का कारण रिजर्व बैंक का वह नियम था, जिसके अंतर्गत निवेशकों के लिए करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए अंडरलाइंग फॉरेन करेंसी एक्सपोजर (विदेशी मुद्रा का वास्तविक लेनदेन या आवश्यकता) का साक्ष्य देना अनिवार्य कर दिया गया था। इस नियम से पहले सट्टेबाज (स्पेक्युलेटर्स) और आम निवेशक बहुत सुगमता से ट्रेड कर पाते थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि जनवरी 2025 से बीएसई के करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में कारोबार लगभग शून्य हो चुका है।

यह उत्पाद निवेशकों को मुद्रा जोखिम के बिना करेंसी जोड़ी में व्यापार करने की अनुमति देगा जैसे यूरो–डॉलर या पाउंड–डॉलर। क्वांटो क्रॉस–करेंसी डेरिवेटिव एक वित्तीय

अनुबंध है। यह निवेशकों को विदेशी मुद्राओं के उतार–चढ़ाव से लाभ अर्जित करने में सहायता करता है। यह अनुबंध विदेशी मुद्राओं की गति पर दृष्टि रखता है जबकि लाभ और हानि का निपटान एक तय 'कन्वर्जन मैकेनिज्म' के अंतर्गत पहले से निश्चित मुद्रा में किया जाता है। 'कन्वर्जन मैकेनिज्म' वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक वित्तीय संपत्ति या मुद्रा पूर्व–निर्धारित शर्तों पर दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निवेशक को अपने लाभ या हानि को अपनी घरेलू मुद्रा में बदलने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। उदाहरण के लिए यदि निवेशक यूरोप की मुद्रा यूरो के बाजार में निवेश करते हैं और यदि क्वांटो का उपयोग करते हैं, तो आपको केवल यूरो के भाव का ध्यान रखना होगा। यदि यूरो मजबूत होता है, तो पूरा लाभ मिलेगा। इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव कब बदल रहा है। निपटान के समय करेंसी बदलने का कोई खतरा नहीं होता। निवेशक बिना सीधे विदेशी मुद्रा खरीदे वैश्विक बाजारों में सीधे ट्रेड कर सकते हैं।

सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी रोज मर्क के चेयरमैन एवं स्वतंत्र निदेशक और वरिष्ठ वित्तीय सेवा क्षेत्र व्यवसायी उदय तरदलकर ने कहा, 'इन अनुबंधों को मात्रा समायोजित (क्वांटिटी एडजस्टेड) कहा जाता है। ये विदेशी निवेशकों के लिए हमारे बाजार में एक अच्छा अवसर हो सकते हैं क्योंकि वे मुद्रा दर तय कर सकेंगे और उन्हें इस पर कोई संभावित हानि भी नहीं उठानी होगी। क्रॉस–करेंसी डेरिवेटिव में संभावित हानि न होना इस तरह के निवेश की सबसे बड़ी विशेषता है।

एनएसई कई अन्य योजनाओं के लिए भी बाजार नियामक से मंजूरी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। इन योजनाओं में जिंस डेरिवेटिव खंड में

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अब एनएसई को आशा है कि बिना करेंसी रिस्क वाले इन 'क्वांटो कॉन्ट्रैक्ट्स' के आने से बड़े संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय निवेशक दोबारा भारतीय बाजारों का रुख करेंगे।

थर्मल कोल अनुबंध है और कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर ब्याज दर डेरेविटिव सम्मिलित हैं। एमसीक्यूब के मैनेजिंग पार्टनर एवं मल्टी–कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के पूर्व एमडी एवं सीईओ मृगांक परांजपे ने कहा कि हेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले अनुबंध स्वागत योग्य हैं। उन्होंने कहा, हमारे देश में मुद्रा और जिंस से जुड़े जोखिम की हेजिंग (यानी जोखिम से सुरक्षा से बचने का उपाय) के बारे में जानकारी की कमी है या लोग इसमें रुचि नहीं लेते। अगर लोगों में रुचि और रुझान हो तो भी योजनाओं की कमी है। एक्सचेंजों को ऐसे कारोबार के बारे में सोचना चाहिए जिसमें संभवतः तुरंत सफलता भले ना मिले, परंतु ऐसी योजनाओं का प्रारम्भ शुभ संकेत है।

भारतीय एक्सचेंजों पर 'क्वांटो क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव' जैसी योजनाएं लाने से निवेशकों को विनियमित घरेलू मंचों के माध्यम से वैश्विक मुद्राओं का व्यापार करने का अवसर मिलेगा। साथ ही इससे भारतीय मुद्रा के साथ एक विदेशी मुद्रा की जोड़ी के अलावा दूसरे अनुबंधों का क्षेत्र बढ़ाकर एक्सचेंज–ट्रेडेड करेंसी (करेंसी डेरिवेटिव) व्यापार पुनः बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। एक विशेषज्ञ ने कहा,'पिछले छह महीनों से बाजार में इस बात पर चर्चा हो रही है कि एक्सचेंजों को यूरो–डॉलर, पाउंड–डॉलर और डॉलर–येन जैसी गैर भारतीय मुद्रा जोड़ी में क्रॉस–करेंसी डेरिवेटिव के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए।' एक सरकारी बैंक के विदेशी मुद्रा डीलर ने कहा, 'बाजार का मानना है कि रुपये के अलावा क्रॉस–करेंसी डेरिवेटिव की अनुमति देने से एक्सचेंजों पर व्यापारिक गतिविधियां फिर बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।'

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अब एनएसई को आशा है कि बिना करेंसी रिस्क वाले इन 'क्वांटो कॉन्ट्रैक्ट्स' के आने से बड़े संस्थागत और अंतरराष्ट्रीय निवेशक दोबारा भारतीय बाजारों का रुख करेंगे। यदि आरबीआई से इसकी स्वीकृति मिलती है, तो यह सेगमेंट एक बार फिर गति पकड़ सकता है। ❑❑

(स्रोत – मनी9लाइव एवं बिज़नस स्टैंडर्ड 6 जुलाई 2026)

भारत-अमेरिका ट्रेड डील

सुस्त चाल के दाव-पेंच

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। दोनों देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ हैं और उनका द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। फिर भी अंतिम व्यापार समझौते पर सहमति बनने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। इसका कारण टैरिफ का विवाद तो है ही बल्कि वैश्विक घटनाओं का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।

अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण एवं आपूर्ति केंद्र के रूप में देखता है। दूसरी ओर, भारत इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है, लेकिन अपने कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों से समझौता किए बिना। इसलिए भारत अपनी मजबूत मोलभाव की स्थिति बनाए हुए है।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा, खाद्यान्न और उर्वरकों की वैश्विक कीमतों को प्रभावित किया है। भारत रूस से ऊर्जा आयात जारी रखे हुए है, जबकि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर रूस से उर्जा आयात में बाधा खड़ी करना चाहता है। अमेरिका को यह भी अंदेशा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिकी रणनीतिकार भारत को रूस और चीन के खिलाफ़ खड़ा तो करना चाहते हैं लेकिन वे भारत के विकास में बाधाएं भी खड़ी कर रहें है ताकि भारत विकास की राह पर सरपट दौड़ न लगाये और एक दिन चीन की तरह अमेरिका को ही आखँे दिखाने लगे।

इज़राइल-ईरान-अमेरिका संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव के कारण समुद्री परिवहन, बीमा लागत और वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। इससे दोनों देश अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय व्यापार व्यवस्था चाहते हैं। अमेरिका अपने किसानों, उद्योगों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना चाहता है। इसलिए वह ऐसे समझौते से बचना चाहता है जिसे घरेलू स्तर पर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़े। इसके अतिरिक्त भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों और समूहों के साथ व्यापार समझौते किए हैं तथा अन्य पर बातचीत जारी है।

भारत की वार्ता रणनीति का उद्देश्य केवल शीघ्र समझौता करना नहीं, बल्कि ऐसा समझौता सुनिश्चित करना है जो विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित"-इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करे।

दुलीचंद कालीरमन

इससे भारत के पास विकल्प बढ़े हैं और वह अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। दुनिया के कई देश अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए शुल्क और गैर–शुल्क बाधाओं का उपयोग कर रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों भी कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में यही दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिससे वार्ता जटिल हो जाती है।

क्या केवल वैश्विक कारणों से ही देरी हो रही है?

भारत की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे ताकि अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकें। दूसरी ओर, भारत को आशंका है कि ऐसा होने पर छोटे किसान और डेयरी उत्पादक अमेरिकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत इस क्षेत्र में अत्यधिक सावधानी बरत रहा है।

अमेरिका दवा, सॉफ्टवेयर और तकनीकी क्षेत्रों में कड़े बौद्धिक संपदा कानून चाहता है। इस कारण भारत के जेनेरिक दवा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत डेटा संप्रभुता का समर्थक है और चाहता है कि भारतीय नागरिकों का संवेदनशील डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे। अमेरिका डेटा के अपेक्षाकृत मुक्त प्रवाह का समर्थन करता है। इस विषय पर भी दोनों देशों के दृष्टिकोण अलग हैं।

भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि समझौते के बाद अमेरिका भविष्य में अचानक नए टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध लागू न करे। दोनों देशों में सरकारों को अपने किसानों, उद्योगों, श्रमिकों और व्यापारिक संगठनों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कोई भी पक्ष जल्दबाजी में समझौता नहीं करना चाहता।

भारत के दृष्टिकोण से ट्रेड डील के लाभ

यदि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर शुल्क कम होता है तो वस्त्र, इंजीनियरिंग, रत्न एवं आभूषण, रसायन और फार्मा उत्पादों का निर्यात बढ़ सकता है। निर्यात बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और उद्योगों में लाखों नए रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में। अमेरिकी कंपनियाँ भारत में नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कर सकती हैं। इससे पूंजी निवेश, रोजगार और आधुनिक तकनीक का विस्तार होगा। अमेरिका अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाना चाहता है। भारत इस रणनीति का प्रमुख लाभार्थी बन सकता है। सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा तकनीक, अंतरिक्ष और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। भारत का आईटी और सेवा क्षेत्र अमेरिकी बाजार में और अधिक अवसर प्राप्त कर सकता है, जिससे सेवा निर्यात बढ़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा से भारतीय उद्योग गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करेंगे। अमेरिकी निवेश और तकनीक से भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत हो सकता है। यदि भारतीय उत्पाद अमेरिकी गुणवत्ता मानकों को पूरा करें, तो मसाले, फल, चावल और समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ सकता है।

ट्रेड डील में संभावित चुनौतियाँ

सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय किसानों के लिए चुनौती बन सकते हैं। अमेरिकी डेयरी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा से छोटे दुग्ध उत्पादकों और सहकारी संस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है। छोटे उद्योगों को बड़ी अमेरिकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। यदि आयात निर्यात से अधिक बढ़ता है, तो भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। व्यापार समझौते की शर्तों के कारण भविष्य में भारत कुछ संरक्षणवादी नीतियाँ आसानी से लागू नहीं कर पाएगा।

अमेरिकी निवेश और तकनीक से भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत हो सकता है।

यदि अमेरिकी कंपनियों को सरकारी परियोजनाओं में अधिक अवसर मिलते हैं, तो भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। डेटा सुरक्षा और डिजिटल नियमों से जुड़े समझौते भारत की डिजिटल नीति को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं और विनिर्माण क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ सकता है।

आगे का रास्ता

भारत की रणनीति यह है कि वह इन वैश्विक परिस्थितियों का लाभ उठाकर बेहतर शर्तें प्राप्त करे, जबकि अमेरिका भारत को एक दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में मजबूत करना चाहता है। यही कारण है कि वार्ता जारी है, लेकिन दोनों पक्ष अपने–अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना संतुलित और टिकाऊ समझौते पर पहुँचना चाहते हैं।

इसलिए भारत की वार्ता रणनीति का उद्देश्य केवल शीघ्र समझौता करना नहीं, बल्कि ऐसा समझौता सुनिश्चित करना है जो विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित"–इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करे। यही कारण है कि वार्ता में समय लग रहा है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से एक संतुलित और टिकाऊ समझौता भारत के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ❑❑

संतुलित होता असंतुलित विकास

स्वतंत्रता के बाद की सरकारों की नीतियों के कारण भारत में आधारभूत संरचना के विकास का दायरा केवल दक्षिण भारत, महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित रहा। परिणामस्वरूप कभी बड़े साम्राज्यों के केंद्र रहे उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों के लिए 'बीमारू' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। 1980 के दशक में जनसांख्यिकीविद् आशीष बोस ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 'बीमारू' प्रदेश कहा था।

यह अविकसित अर्थव्यवस्था, कमजोर अवसंरचना विकास, निर्धनता, निरक्षरता के परिणामस्वरूप जनसंख्या–विस्फोट, उच्च शिशु–मृत्यु तथा दुर्बल स्वास्थ्य से ग्रस्त प्रदेशों की संरचनात्मक जड़ता के सांकेतिक बोधक के रूप में रहा। वास्तविकता में इस स्थिति का विस्तार उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों तक रहा। जहां भारत की बड़ी आबादी विकास के पैमानों में पीछे रही। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार राज्यों के सहयोग से इन क्षेत्रों की बदहाली को दूर करने में बहुत हद तक सफल रही है।

हवाई संपर्क की बात करें तो 2014 से पहले देश में लगभग 74–75 परिचालन हवाई अड्डे थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो चुकी है। इनमें कई नए या पुनर्जीवित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे शामिल हैं, जैसे नोएडा (जेवर), मोपा (गोवा), शिवमोग्गा (कर्नाटक), होल्लोंगी (अरुणाचल प्रदेश), राजकोट (हिरासर) और अयोध्या प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हवाई संपर्क का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

2014 तक भारत में लगभग 1,000–1,300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे थे, जबकि अब यह नेटवर्क 6,000 किमी से अधिक हो चुका है। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, बुंदेलखंड,

स्वतंत्रता के बाद भारत में क्षेत्रीय असंतुलित विकास को मोदी सरकार ने आधारभूत संरचना के विस्तार से संतुलित किया है। हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास से उत्तर, पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में प्रगति हुई है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं।

मुनि शंकर पाण्डेय

गंगा, दिल्ली–देहरादून और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट उत्तर भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। पहले जहां आधुनिक एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पश्चिमी और दक्षिणी भारत में केंद्रित था, वहीं अब उत्तर और पूर्वी भारत भी तेजी से इस नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने विकेंद्रित ढांचागत निर्माण की नीति को ऊर्जा क्षेत्र में भी लागू किया।

देश में नई रिफाइनरी परियोजनाओं के साथ–साथ मौजूदा रिफाइनरियों का विस्तार किया गया है। विशेष रूप से जोधपुर में रिफाइनरी का शिलान्यास, बरौनी रिफाइनरी (बिहार) का उन्नयन, पानीपत रिफाइनरी (हरियाणा) का विस्तार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश इस बदलाव के उदाहरण हैं। इसके साथ ही ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन, जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा पाइपलाइन, नार्थ–ईस्ट गैस ग्रिड और अन्य परियोजनाओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर राज्यों तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड जैसी भारत सरकार की कंपनियों को आगे किया।

वर्तमान भारत के औद्योगिक राजनीतिक भूगोल में इस समय एक बड़ा परिवर्तन चुपचाप आकार ले रहा है। लंबे समय से देश के आटोमोबाइल उद्योग का केंद्र दक्षिण और पश्चिम भारत रहा है। तमिलनाडु को डेट्रायट आफ इंडिया कहा गया, जबकि गुजरात ने बीते डेढ़ दशक में गतिशील औद्योगिक नीति के बल पर वैश्विक वाहन कंपनियों को आकर्षित कर देश के सबसे बड़े आटो हब में अपनी जगह बना ली, परंतु अब उत्तर भारत में एक नया औद्योगिक भूगोल तेजी से उभर रहा है, जिसके केंद्र में उत्तर एवं मध्य के राज्य और पूर्वोत्तर भारत हैं।

केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इन कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार एक्सप्रेसवे, समर्पित मालवाहक गलियारों, बहुस्तरीय परिवहन केंद्रों, हवाई अड्डों तथा औद्योगिक समूह क्षेत्रों का विस्तार किया है, उसने राज्य की आर्थिक छवि को परिवर्तित करना आरंभ कर दिया है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के जापान सहित अन्य प्रमुख वैश्विक वाहन विनिर्माता देशों के साथ हुए समझौते केवल निवेश आकर्षित करने का प्रयास नहीं हैं।

इनके पीछे उत्तर प्रदेश की वह दीर्घकालिक रणनीति है, जो राज्य को केवल असेंबल इकोनमी से आगे ले जाते हुए समेकित निर्माण व्यवस्था में रूपांतरित करना चाहती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र इस परिवर्तन के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं। एक समय यह क्षेत्र केवल आवासीय विस्तार और भू–संपदा के लिए चर्चित था, किंतु आज यहां इलेक्ट्रानिक उपकरण, ऊर्जा संचयन प्रणाली, वाहन कलपुर्जे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स–ईवी जैसे उद्योग तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं।

इस संपूर्ण परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। औद्योगिक इतिहास साक्षी है कि जिन क्षेत्रों ने परिवहन और आपूर्ति तंत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, वही वैश्विक निर्माण शक्ति बने। गुजरात को समुद्री बंदरगाहों का लाभ प्राप्त हुआ, तमिलनाडु को चेन्नई बंदरगाह ने सामर्थ्य प्रदान की।

कुल मिलाकर, पिछले एक दशक में नीति का फोकस अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर की ओर बढ़ा है। इससे परिवहन सुविधाएं बढ़ी हैं, क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं, निवेश आकर्षित हो रहे हैं और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ है। बड़े बंदरगाह, औद्योगिक गलियारे और ऊर्जा अवसंरचना पश्चिमी और दक्षिणी भारत के साथ उत्तर भारत में दस्तक दे रहे हैं। ❑❑

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार और लोक–नीति विश्लेषक हैं)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

भारत–जापान की नई रणनीतिक साझेदारी से बदलेंगे एशिया के शक्ति समीकरण

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी 'छोटी बहन' कहकर संबोधित किया, तब यह केवल शिष्टाचार का एक वाक्य नहीं था। कूटनीति की दुनिया में शब्द अक्सर दस्तावेजों से ज्यादा गहरे संदेश देते हैं। इस संबोधन के पीछे वह भरोसा छिपा था, जिसे भारत और जापान ने पिछले ढाई दशकों में धीरे–धीरे तैयार किया है। लेकिन इस मुलाकात की असली अहमियत भावनात्मक रिश्ते से कहीं आगे है। यह उस दौर में हुई है, जब एशिया की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी है, चीन का बढ़ता दबदबा पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ा रहा है, वैश्विक सप्लाई चेन नए ठिकाने तलाश रही है और तकनीक भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ऐसे समय में भारत और जापान ने दुनिया को यह संकेत दिया है कि दोनों देशों की साझेदारी अब केवल निवेश और व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और सामरिक सुरक्षा की नई धुरी बनने जा रही है।

भारत और जापान के रिश्तों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि इनमें कभी उतार–चढ़ाव की राजनीति नहीं दिखी। 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास लगातार बढ़ता गया। 2000 में रिश्तों को नई दिशा मिली, 2006 में उन्हें 'स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप' का दर्जा मिला और 2014 में इन्हें 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप' में बदल दिया गया। यह वही दौर था, जब जापान ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एशिया में सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखना शुरू किया। दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मेट्रो परियोजनाएं और औद्योगिक टाउनशिप जैसे दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट इसी सोच का परिणाम हैं। जापान ने पिछले दो दशकों में भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया और आज करीब 1,400 जापानी कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय हैं।

आने वाले वर्षों में यह साझेदारी केवल भारत और जापान की नहीं, बल्कि पूरे इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की दिशा तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में गिनी जा सकती है।

– अजय कुमार

लेकिन इस बार का शिखर सम्मेलन इसलिए अलग था क्योंकि पहली बार दोनों देशों ने रक्षा सह–विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब तक भारत और जापान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, रक्षा संवाद और समुद्री सुरक्षा तक सहयोग कर रहे थे, लेकिन रक्षा तकनीक के संयुक्त विकास की दिशा में यह पहला कदम है। इसका मतलब केवल हथियार बनाना नहीं है। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में दोनों देश ऐसी तकनीकों पर साथ काम करेंगे, जो समुद्री निगरानी, सुरक्षित संचार, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रक्षा प्रणाली और भविष्य की युद्ध तकनीकों की दिशा तय करेंगी। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत–जापान संबंधों का सबसे बड़ा रणनीतिक मोड़ मान रहे हैं, क्योंकि जापान लंबे समय तक रक्षा निर्यात और सैन्य तकनीक साझा करने में बेहद सतर्क रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता सबसे बड़ा कारण है। पिछले एक दशक में दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, ताइवान के आसपास लगातार सैन्य अभ्यास, पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों को लेकर जापान के साथ तनाव और हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने पूरे इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बदल दी है। दूसरी ओर, भारत

भी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लंबे सैन्य गतिरोध का सामना कर चुका है। ऐसे में नई दिल्ली और टोक्यो की रणनीतिक सोच पहले से कहीं ज्यादा समान दिखाई देती है। दोनों देश मानते हैं कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और नियम–आधारित व्यवस्था ही एशिया में स्थिरता बनाए रख सकती है। यही वजह है कि क्वाड के भीतर भी भारत और जापान सबसे सक्रिय साझेदारों में गिने जाते हैं।

रक्षा सहयोग के साथ–साथ आर्थिक सुरक्षा इस शिखर सम्मेलन का दूसरा सबसे बड़ा विषय रही। कोविड महामारी और उसके बाद रूस–यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को यह सिखाया कि केवल सस्ती सप्लाई चेन पर्याप्त नहीं होती, बल्कि भरोसेमंद साझेदार भी जरूरी होते हैं। लंबे समय तक दुनिया का अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन चीन पर निर्भर रहा, लेकिन अब अमेरिका, जापान, भारत और यूरोप वैकल्पिक सप्लाई नेटवर्क तैयार करने में जुटे हैं। इसी रणनीति के तहत भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और उन्नत विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। आज दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था चिप्स पर टिकी है और जापान इस क्षेत्र में कच्चे माल, मशीनरी तथा तकनीक का बड़ा केंद्र है, जबकि भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का नया हब बन रहा है। दोनों देशों की साझेदारी भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा में निर्णायक साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान बताया कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के बीच लगभग 120 नए कारोबारी समझौते हुए हैं। अब लक्ष्य अगले दस वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन का जापानी निवेश आकर्षित करना

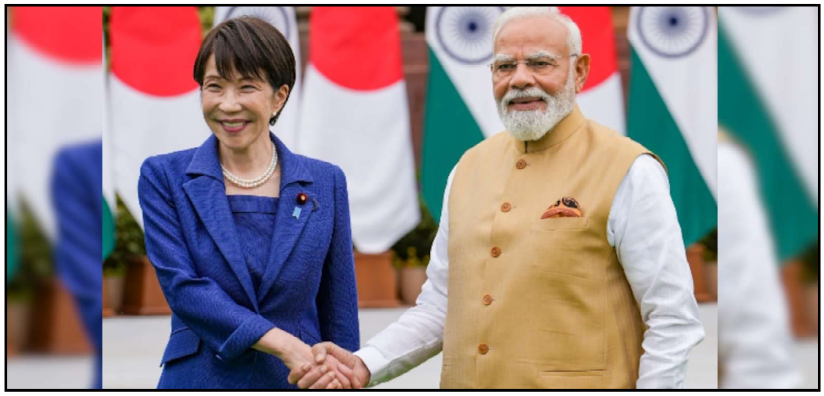

है। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब छह लाख करोड़ रुपये से अधिक बैठती है। यह निवेश केवल कारखाने लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, बैटरी तकनीक और हाई–टेक उद्योगों में भी लगाया जाएगा। वर्ष 2025–26 में भारत–जापान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन दोनों सरकारें मानती हैं कि यह क्षमता के मुकाबले अभी भी काफी कम है। इसलिए अब निवेश और व्यापार दोनों को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है।

शिखर सम्मेलन में हरित ऊर्जा को भी नई प्राथमिकता मिली। 'गोवर्धन' पहल के तहत भारत–जापान बायोगैस मिशन शुरू किया गया है, जिसके जरिए आधुनिक बायोगैस संयंत्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसका मकसद केवल स्वच्छ ऊर्जा पैदा करना नहीं है, बल्कि कृषि अवशेषों का बेहतर उपयोग, किसानों की अतिरिक्त आय, जैविक उर्वरकों का उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भी है। जापान की पर्यावरणीय तकनीक और भारत की विशाल कृषि अर्थव्यवस्था का यह मेल आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास का नया मॉडल बन सकता है। तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देशों की सोच तेजी से बदल रही है। अब सहयोग केवल हार्डवेयर या मशीनों तक सीमित नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, 6जी संचार, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी संयुक्त अनुसंधान का रास्ता खोला गया है। जापान के पास उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग और सटीक विनिर्माण की क्षमता है, जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल प्रतिभा और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता है। यदि दोनों की ताकतें एक मंच पर आती हैं, तो एशिया में तकनीकी नेतृत्व का नया केंद्र उभर सकता है।

2027 में भारत और जापान अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे करेंगे। लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि आने वाला दशक केवल दोस्ती का नहीं, बल्कि साझा नेतृत्व का दशक होगा। बदलती वैश्विक राजनीति में, जहां कई पुराने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं, वहीं भारत और जापान का रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि नई दिल्ली में बोला गया 'छोटी बहन; का एक वाक्य केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि उस रणनीतिक विश्वास का प्रतीक बन गया, जिसके सहारे दोनों देश एशिया की नई शक्ति संरचना को आकार देने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी केवल भारत और जापान की नहीं, बल्कि पूरे इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की दिशा तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में गिनी जा सकती है। ❑❑

डिजिटल डेटा सुरक्षा के लिए बने कारगर कानून

दुनिया के कई विकसित देशों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जा रहे है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को हिंसक, झूठे और भ्रामक कंटेंट से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। ऐसा कंटेंट उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। दरअसल, तमाम चिंताओं के बावजूद बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। बाजार भी उन्हें टारगेट करते हुए लुभावना कंटेंट पेश कर रहा है। डिजिटल इकॉनमी में बच्चे अब केवल उपभोक्ता नहीं रह गए है बल्कि उनकी पसंद–नापसंद और व्यवहार संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। कंपनियों का मुनाफा बच्चों को अधिक से अधिक समय तक ऑनलाइन बनाए रखने से बढ़ता है।

दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा ऑनलाइन आबादियों में से एक होने के कारण भारत के पास यह अवसर है कि वह ऐसा डिजिटल तकनीकी इनोवेशन जितना महत्वपूर्ण शासन मॉडल विकसित करे जिसमें बच्चों के अधिकार और सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

इंटरनेट की मजबूत पकड़

एएसईआर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 14 से 16 वर्ष की उम्र के 89 प्रतिशत किशोरों के घर में स्मार्टफोन है। इनमें से 76 प्रतिशत सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा सुबह उठते ही मोबाइल फोन उठा ले। नाश्ते की मेज तक पहुंचने से पहले ही कई डिजिटल प्लैटफॉर्म्स के अल्गोरिदम उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की होड़ में लग जाएं। बच्चे का हर स्क्रॉल, हर स्वाइप और हर सर्च रेकॉर्ड हो। फिर उसका विश्लेषण कर उसे आर्थिक मूल्य में बदल दिया जाए। हैरानी की बात है कि यह पूरी प्रक्रिया महज 50 से 100 मिलीसेकंड में पूरी हो रही है।

ज्यादातर डिजिटल प्लैटफॉर्म या तो मुफ्त हैं या उनकी सदस्यता फीस बहुत कम है, क्योंकि उनका असली उत्पाद स्वयं उपयोगकर्ता होता है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बच्चे अधिक से अधिक समय तक इनसे जुड़े रहें। बच्चों के व्यवहार से जुड़ा डेटा बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते हैं। आज के दौर में आपका ध्यान ही सबसे मूल्यवान करंसी है। बच्चों का ध्यान और भी कीमती है, क्योंकि उसी से भविष्य के उपभोक्ताओं को आकार दिया जा सकता है। अर्थशास्त्री और समाज वैज्ञानिक हर्बर्ट साइमन ने कहा था कि जानकारी की अधिकता, ध्यान की कमी पैदा करती है। एआई और चैटबॉट्स के युग में बच्चों के लिए सही और उपयोगी जानकारी चुनना अब भी चुनौती बना हुआ है।

बच्चे नहीं वयस्क उपभोक्ता

विभिन्न ऐप्स द्वारा अनंत स्क्रॉलिंग, ऑटो–प्ले और उपयोगकर्ता को तरह–तरह के डिजिटल पुरस्कार देने जैसी सुविधाएं कोई संयोग नहीं है। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि उपयोगकर्ता लगातार स्क्रीन पर बना रहे। वहीं, बच्चों की निर्णय लेने और आवेगों को

नियंत्रित करने की क्षमता अभी विकसित हो रही है, इसलिए वे ऐसे डिजिटल प्रलोभनों के प्रति आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। उन पर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोनाथन का कहना है कि बचपन अब 'खेल आधारित' होने के बजाय 'फोन आधारित' होता जा रहा है।

स्मार्टफोन और सोशल मीडिया बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। यूनिसेफ इंडिया की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल तकनीक ने शिक्षा और भागीदारी के नए अवसर तो दिए है, लेकिन निजता के लिए खतरा, व्यावसायिक शोषण और ऑनलाइन नुकसान की ओर धकेला भी है। इसलिए, बच्चों को केंद्र में रखकर डिजिटल गवर्नेंस की आवश्यकता है। डिजिटल युग में बचपन की रक्षा केवल डिजिटल साक्षरता से नहीं होगी। इसके लिए यह समझना होगा कि ध्यान केवल व्यापारिक संसाधन नहीं है, बल्कि बच्चों के विकास की एक बुनियादी जरूरत भी है।

सवाल है कि बच्चों को इससे बचने की जिम्मेदारी किसकी है। क्या डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी केवल माता–पिता की है? या सरकार और तकनीकी कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है? दुनिया के कई देशों में नीति–निर्माता अब इस समस्या को गंभीरता से ले रहे है। ब्रिटेन की आयु–उपयुक्त डिजाइन संहिता और यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम मानते है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल माता–पिता की नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों की भी है।

इस बीच फ्रांस की संसद ने भी 15 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला विधेयक पास कर दिया है। इसके साथ ही फ्रांस यूरोपीय संघ में यह कानून लागू करने वाले अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। इस बाबत वहां की उच्च और निचले सदन की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि वहां के वामपंथी दल अभी भी विरोध कर रहे हैं लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए फ्रांस ने सोशल मीडिया पर बैन का मन बना लिया है।

असल सवाल यह है कि क्या ऐसे आर्थिक मॉडल पर सीमाएं लगाने की तैयारी है। भारत जैसे देश में, जहां सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने बच्चों की डिजिटल दुनिया में पहुंच को बहुत बढ़ा दिया है। चुनौती यह नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन हों या नहीं, बल्कि यह है कि डिजिटल पहुंच के साथ–साथ उनकी डिजिटल सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा ऑनलाइन आबादियों में से एक होने के कारण भारत के पास यह अवसर है कि वह ऐसा डिजिटल तकनीकी इनोवेशन जितना महत्वपूर्ण शासन मॉडल विकसित करे, जिसमें बच्चों के अधिकार और सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

भारत में चली पहली हाइड्रोजन ट्रेन

भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जींद से सोनीपत तक चली। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने अपने–अपने अनुभव भी साझा किये। हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात के साथ–साथ हरियाणा पंजाब के दौरे पर गए मोदी ने 'अमृत भारत योजना' के तहत विकसित 75 अलग–अलग रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने दौरे के दौरान 26000 करोड रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद चंडीगढ़ हरियाणा के जींद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह रेलवे, स्वास्थ्य सेवाओं, संपर्क और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में हिस्सा आगे भी लेते रहेंगे जिससे कि देश के युवाओं किसानों कामगारों महिलाओं के जीवन पर बेहद सकारात्मक असर पड़े। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में सवार कई स्कूली बच्चों ने अपने–अपने अनुभव अपने–अपने तरीके से साझा किये। जींद के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया तथा गर्व व्यक्त किया। वहां के एक नागरिक ने बातचीत में बताया कि उनके इलाके के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है। पहली हाइड्रोजन चलने के कारण जींद देश भर में मशहूर हो गया है। जींद के अधिकांश निवासियों ने प्रधानमंत्री के इस प्रयास की दिल खोलकर सराहना की।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को एक उपलब्धि बताते हुए कहा गया कि यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल रहेगी इससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। यह ट्रेन डीजल या पारंपरिक बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है। ट्रेन में हाई प्रेशर टैंकों से भरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बिजली पैदा करती रहती है।

मालूम हो कि भारत में रेल का सफर भाप के इंजन से शुरू होकर आधुनिक बंदे भारत, नमो भारत, व्यापक रेल विद्युतीकरण और तेज रफ्तार की अन्य गाड़ियों के साथ–साथ आज

पहली हाइड्रोजन चलने के कारण जींद देश भर में मशहूर हो गया है। जींद के अधिकांश निवासियों ने प्रधानमंत्री के इस प्रयास की दिल खोलकर सराहना की।

– गौरी तिवारी

हाइड्रोजन से चलने वाली रेल तक पहुंच चुका है। यह केवल तकनीक का विकास नहीं बल्कि तेज, सुरक्षित, हरित और आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी जब देश की पहली ट्रेन मुंबई से थाणे के बीच चली थी। यह पहली यात्रा 34 किलोमीटर लंबी थी जिसे तीन भाप के इंजन (साहब, सुल्तान और सिंध) ने पूरा किया था। इस पहली गाड़ी में लगभग 400 लोग सवार थे। इस यात्रा ने भारत में परिवहन के एक नए युग की शुरुआत कर दी। भारत में यह आसान नहीं था। अंग्रेजों ने इसे अपनी व्यापारिक और प्रशासनिक सुविधा के लिए शुरू किया था। शुरुआती दिनों में इसका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देना था। वर्ष 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच ट्रेन चलाई गई और धीरे–धीरे पूरे देश में रेलवे का जाल फैलता गया।

1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने रेलवे का इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों की तेज आवाजाही के लिए किया। लेकिन इसी दौरान भारतीयों ने भी समझ लिया कि रेल सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि संचार और संगठन का भी महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। 19वीं सदी के अंत तक भारत के कई प्रमुख रेल मार्ग विकसित हो चुके थे। 1870 में पहली बार मुंबई से कोलकाता तक ट्रेन चली जिससे पूरे देश को आपस में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। 20वीं सदी में भारतीय रेल का उपयोग न केवल व्यापार और प्रशासन के लिए बल्कि देश की एकता और आंदोलन के लिए भी शुरू हो गया। गांधी जी ने अपने आंदोलन के दौरान ट्रेनों का भरपूर उपयोग किया। वह तीसरी श्रेणी में यात्रा करते थे और भारतीयों की दुर्दशा को नजदीक से देखते–समझते थे। गांधी जी ने तब कहा था कि रेल केवल लोहे का ढांचा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है।

1947 में जब भारत आजाद हुआ तो रेलवे भी एक बड़ी चुनौती के रूप में था। विभाजन के दौरान लाखों लोग रेल से इधर–उधर गए। दर्दनाक घटनाओं के बावजूद रेलवे ने लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखा। आजादी के बाद रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया। स्टीम इंजन की जगह डीजल और फिर इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली। 1986 में पहली बार भारतीय रेलवे ने कंप्यूटर आधारित आरक्षण प्रणाली शुरू की। 21वीं सदी में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जाने लगा। 2014 में सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस चली और फिर बंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों ने भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन दो करोड़ से अधिक लोग सफर करते हैं। यह केवल परिवहन प्रणाली नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति समाज और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूरज भारद्वाज प्रतिदिन रेल द्वारा बागपत से पुरानी दिल्ली आते हैं और फिर पुरानी दिल्ली से हंसते गाते हुए अपने गांव के स्टेशन पर वापस लौट जाते हैं। रेलवे प्लेटफार्म पर बिकती गरम चाय, ट्रेन की खिड़की से बिकते स्थानीय पकवान, भजन कीर्तन और ताश के पत्तों के साथ रोज का सफर तय करती स्थानीय जनता या स्टेशन पर गूंजती, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफार्म नंबर एक पर आने वाली गाड़ी आप प्लेटफार्म नंबर तीन से रवाना होगी.... की आवाज–सब कुछ मिलाकर रेल सफर की ऐसी यादें होती है, जो हर यात्री के दिल में बस जाती है। भारतीय रेल का सफर केवल पटरी पर चलने वाली गाड़ियों का नहीं बल्कि समय के साथ बढ़ते भारत की कहानी भी है। यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि हर रोज नए यात्रियों, नए स्टेशनों नई गाड़ियों, नई तकनीक और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहेगी। आप भी गर्व करिए कि अब भारत की यात्रा जो भाप के इंजन से शुरू हुई थी हाइड्रोजन का मुकाम हासिल कर चुकी है। छुक–छुक करती चलती ट्रेन विकास की सीढ़ी चढ़ते हुए भारतवासियों को हर दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती रहेगी। ❑❑

भारतीय रेल का सफर केवल पटरी पर चलने वाली गाड़ियों का नहीं बल्कि समय के साथ बढ़ते भारत की कहानी भी है। यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि हर रोज नए यात्रियों, नए स्टेशनों नई गाड़ियों, नई तकनीक और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहेगी।

विदेश से भारत की संप्रभुता-सुरक्षा के खिलाफ डिजिटल वार

दुनिया में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कभी देशों को कमजोर करने के लिए सीमा पर सेना उतारी जाती थी, अब वही काम मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए किया जा रहा है। अब युद्ध में न तो टैंक दिखाई देते हैं और न ही मिसाइलें, लेकिन इसका असर किसी पारंपरिक युद्ध से कम नहीं होता। इसका लक्ष्य दुश्मन के शहरों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसके समाज में अविश्वास, भय और विभाजन पैदा करना होता है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ–साथ सबसे बड़ा डिजिटल समाज भी बन चुका है, पिछले एक दशक से इसी अदृश्य युद्ध का प्रमुख निशाना बना हुआ है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जबकि सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। हर दिन करोड़ों भारतीय मोबाइल पर समाचार देखते हैं, राय बनाते हैं और उसे आगे भी भेजते हैं। यही वजह है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है, जहां सूचना को हथियार बनाकर सामाजिक माहौल प्रभावित करने की सबसे अधिक कोशिश होती है। सुरक्षा एजेंसियां कई बार संकेत दे चुकी हैं कि सीमा पार बैठे संगठित नेटवर्क भारतीय नामों, तस्वीरों और स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल कर ऐसे फर्जी खाते तैयार करते हैं, जिन्हें देखकर सामान्य व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि उसके सामने बैठा व्यक्ति वास्तव में किसी दूसरे देश से अभियान चला रहा है।

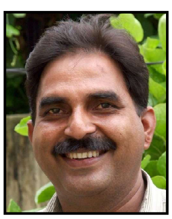

डिजिटल युद्ध का उद्देश्य केवल झूठ फैलाना नहीं, बल्कि भारतीयों के बीच भरोसा खत्म करना है। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक और स्वचालित प्रचार तंत्र इस चुनौती को और गंभीर बनाएंगे।

– **संजय सक्सेना**

इस डिजिटल हमले की पहली गंभीर झलक 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में दिखाई दी। हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान का नहीं, बल्कि दूसरे देश का एक पुराना वीडियो उत्तर प्रदेश का बताकर प्रसारित किया गया। जांच में वीडियो फर्जी निकला, लेकिन तब तक समाज में तनाव फैल चुका था। यही वह दौर था जब पहली बार यह महसूस किया गया कि मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाला झूठ जमीन पर खून–खराबे की वजह बन सकता है। इसके बाद 2017 और 2018 में बच्चा चोरी की अफवाहों ने पूरे देश को झकझोर दिया। व्हाट्सएप पर कुछ सेकंड के वीडियो और झूठे संदेशों ने ऐसी दहशत फैलाई कि असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, त्रिपुरा और तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में भीड़ ने निर्दोष लोगों को बच्चा चोर समझकर पीट–पीटकर मार डाला। पुलिस जांच में अधिकांश मामलों में कोई संगठित बच्चा चोरी गिरोह नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि सच की कोई कीमत नहीं रह गई थी।

कोरोना महामारी के दौरान यह सूचना युद्ध और खतरनाक हो गया। किसी समुदाय को संक्रमण फैलाने वाला बताया गया, कहीं झूठे घरेलू इलाज वायरल किए गए, तो कहीं

वैक्सीन को लेकर तरह–तरह की अफवाहें फैलाई गईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 'इन्फोडेमिक' कहा, यानी ऐसी महामारी जिसमें बीमारी से ज्यादा झूठ फैलता है। भारत में भी करोड़ों लोगों तक ऐसे संदेश पहुंचे जिनका चिकित्सा विज्ञान से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून, दिल्ली हिंसा और किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पूरी तरह राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गया। वास्तविक मुद्दों के साथ–साथ हजारों ऐसे वीडियो और तस्वीरें साझा की गईं जिनका घटना से कोई संबंध नहीं था। कुछ पुराने वीडियो नए बताकर वायरल किए गए तो कुछ तस्वीरों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया गया। किसान आंदोलन के दौरान तथाकथित टूलकिट विवाद ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या भारत के आंतरिक आंदोलनों को विदेशी डिजिटल नेटवर्क दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने कई डिजिटल कड़ियों की जांच की और यह स्पष्ट हुआ कि सोशल मीडिया अब केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि रणनीतिक अभियान चलाने का औजार भी बन चुका है।

2023 में मणिपुर हिंसा ने इस खतरे को और स्पष्ट कर दिया। कई ऐसे वीडियो, जो महीनों पुराने थे या दूसरे देशों के थे, उन्हें मणिपुर का बताकर वायरल किया गया। एक फर्जी वीडियो ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के मन में भी गुस्सा और अविश्वास पैदा कर दिया। यह दिखाता है कि डिजिटल दुष्प्रचार अब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश का माहौल प्रभावित कर सकता है। 2024 के आम चुनावों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस युद्ध को नया आयाम दिया। नेताओं की आवाज बदलकर भाषण तैयार किए गए, नकली वीडियो बनाए गए और ऐसे संदेश प्रसारित किए गए जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से पहचान नहीं सकता था। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि आने वाले वर्षों में डीपफेक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव ने इस खतरे को वास्तविक रूप में सामने ला दिया। जैसे ही सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हुईं, सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो की बाढ़ आ गई। गाजा युद्ध के दृश्य भारत–पाक संघर्ष बताकर चलाए गए। पुराने विस्फोटों के वीडियो को ताजा सैन्य कार्रवाई बताया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार तस्वीरों ने भ्रम और बढ़ा दिया। कुछ विदेशी खातों ने भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के झूठे दावे किए, जबकि दूसरी ओर भारतीय कार्रवाई को लेकर भी मनगढ़ंत वीडियो फैलाए गए। बाद में सरकारी एजेंसियों ने ऐसे अनेक दावों का खंडन किया और बड़ी मात्रा में भ्रामक सामग्री को हटाने की कार्रवाई की।

विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक डिजिटल युद्ध का सबसे बड़ा हथियार 'बॉट नेटवर्क' हैं। हजारों स्वचालित खाते एक ही समय में एक जैसा संदेश प्रसारित करते हैं। इससे किसी झूठे विषय को भी ऐसा दिखाया जाता है, जैसे पूरा देश उसी पर चर्चा कर रहा हो। इसके साथ ही भुगतान लेकर काम करने वाले ट्रोल समूह, नकली समाचार वेबसाइटें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि सामान्य नागरिक के लिए सच और झूठ में अंतर करना कठिन हो जाता है। इस पूरे खेल का आर्थिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सोशल मीडिया पर जितना अधिक विवाद होगा, उतनी अधिक पहुंच मिलेगी। पहुंच बढ़ेगी तो विज्ञापन और कमाई भी बढ़ेगी। यही कारण है कि कुछ प्रभावशाली खाते बिना किसी सत्यापन के सनसनीखेज सामग्री साझा करते हैं। कई बार उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनका साझा किया गया संदेश किसी विदेशी दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा बन चुका है।

भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को सख्त बनाया, सोशल मीडिया मंचों की जवाबदेही बढ़ाई और डीपफेक जैसी नई चुनौतियों को लेकर लगातार परामर्श जारी किए। साइबर सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता भी बढ़ाई गई है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल कानून से इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। जब तक नागरिक स्वयं डिजिटल रूप से जागरूक नहीं होंगे, तब तक किसी भी विदेशी अभियान को रोकना कठिन रहेगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता डिजिटल साक्षरता की है। लोगों को यह सिखाना होगा कि किसी वीडियो का स्रोत कैसे जांचें, किसी तस्वीर की वास्तविकता कैसे परखें और किसी वायरल संदेश पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक पुष्टि क्यों जरूरी है। यदि समाज तथ्य जांच की आदत विकसित कर ले, तो दुष्प्रचार की सबसे मजबूत कड़ी अपने आप टूट जाएगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता है। इसलिए विदेशी दुष्प्रचार का पहला निशाना भी यही बनता है। डिजिटल युद्ध का उद्देश्य केवल झूठ फैलाना नहीं, बल्कि भारतीयों के बीच भरोसा खत्म करना है। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक और स्वचालित प्रचार तंत्र इस चुनौती को और गंभीर बनाएंगे। ऐसे दौर में सीमा पर तैनात सैनिक जितने आवश्यक हैं, उतना ही जरूरी हर वह नागरिक भी है जो मोबाइल पर आए हर संदेश को आंख बंद करके सच नहीं मानता। आधुनिक भारत की सुरक्षा अब केवल सीमा चौकियों पर नहीं, बल्कि हर हाथ में मौजूद मोबाइल स्क्रीन पर भी तय होगी। ❑❑

नशा मुक्ति उपचारः स्वस्थ जीवन की ओर लौटने का मार्ग

नशे की लत आज दुनिया की सबसे गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों में से एक है। शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ, जुआ, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग भी कई बार नशा का रूप ले लेता है। नशा केवल व्यक्ति के शरीर को ही नहीं, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंधों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करता है।

सकारात्मक बात यह है कि नशे की लत का सफलतापूर्वक उपचार संभव है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नशा कोई चरित्र की कमजोरी या इच्छाशक्ति की कमी नहीं, बल्कि मस्तिष्क और व्यवहार से जुड़ी एक जटिल चिकित्सीय स्थिति है। उचित उपचार, परामर्श, परिवार के सहयोग और निरंतर प्रयास से व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ जीवन की ओर लौट सकता है।

नशा कैसे बनता है?

जब कोई व्यक्ति बार–बार किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो मस्तिष्क के पुरस्कार (रिवॉर्ड) तंत्र में परिवर्तन होने लगते हैं। डोपामिन नामक रसायन के प्रभाव के कारण व्यक्ति को बार–बार उसी अनुभव की इच्छा होती है। धीरे–धीरे सहनशीलता (टॉलरेंस) बढ़ती जाती है और पहले जितना आनंद पाने के लिए अधिक मात्रा या अधिक समय तक उस नशा की आवश्यकता महसूस होती है। यही स्थिति धीरे–धीरे नशा का रूप ले लेती है।

नशे की लत जीवन का अंत नहीं है। सही समय पर उपचार, मजबूत इच्छाशक्ति, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति को नई शुरुआत करने का अवसर दे सकता है।

– डॉ. विजय गर्ग

डिटॉक्सिफिकेशन (शरीर से नशे का प्रभाव हटाना)

नशा मुक्ति उपचार का पहला चरण डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इसमें चिकित्सकों की देखरेख में शरीर से नशीले पदार्थों को धीरे–धीरे बाहर निकाला जाता है। कई बार नशा अचानक छोड़ने से गंभीर शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए यह प्रक्रिया विशेषज्ञों की निगरानी में ही की जाती है।

संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (Cognitive Behavioral Therapy & CBT)

सीबीटी नशा मुक्ति की सबसे प्रभावी उपचार पद्धतियों में से एक है। इसमें व्यक्ति को उन विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों की पहचान करना सिखाया जाता है जो उसे नशे की ओर ले जाती हैं। इसके बाद स्वस्थ सोच और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने पर काम किया जाता है।

इस चिकित्सा से व्यक्ति –

- नशे के कारणों को समझता है।
- तनाव से निपटने के बेहतर तरीके सीखता है।
- नशे की तीव्र इच्छा को नियंत्रित करना सीखता है।
- दोबारा नशे की ओर लौटने की संभावना कम करता है।

प्रेरक परामर्श (Motivational Interviewing)

कई लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। प्रेरक परामर्श के माध्यम से विशेषज्ञ व्यक्ति को स्वयं परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। यह उपचार व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और जीवन में बदलाव लाने की इच्छा को मजबूत बनाता है।

दवाइयों द्वारा उपचार

कुछ प्रकार के नशों में दवाइयाँ:

- नशे की इच्छा को कम करती हैं।
- नशा छोड़ने पर होने वाली तकलीफों को नियंत्रित करती हैं।
- दोबारा नशा करने की संभावना को कम करती हैं।

दवाइयों का उपयोग केवल योग्य चिकित्सक की सलाह और निगरानी में ही किया जाना चाहिए।

समूह चिकित्सा

समूह चिकित्सा में नशा छोड़ने का प्रयास कर रहे लोग एक–दूसरे के अनुभव साझा करते हैं। इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। समूह का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाता है, प्रेरणा देता है और लंबे समय तक नशामुक्त रहने में सहायता करता है।

पारिवारिक चिकित्सा

नशे की समस्या केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। पारिवारिक चिकित्सा द्वारा परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग को मजबूत किया जाता है। परिवार का सकारात्मक सहयोग उपचार की सफलता की संभावना को काफी बढ़ा देता है।

डिजिटल और ऑनलाइन उपचार

डिजिटल तकनीक ने नशा मुक्ति उपचार को अधिक सुलभ बना दिया है। आज टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन परामर्श, मोबाइल ऐप, डिजिटल सीबीटी कार्यक्रम और ऑनलाइन सहायता समूहों के माध्यम से लोग घर बैठे विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के लोगों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रहा है।

योग, ध्यान और समग्र उपचार

आज अनेक नशा मुक्ति केंद्र पारंपरिक उपचार के साथ–साथ योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, संगीत चिकित्सा, कला चिकित्सा और प्रकृति आधारित गतिविधियों को भी अपनाते हैं। इनसे तनाव कम करने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्म–नियंत्रण बढ़ाने में मदद मिलती हैं।

व्यवहार संबंधी लतों का उपचार

हर लत किसी नशीले पदार्थ से जुड़ी नहीं होती। आज मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, जुआ और अनियंत्रित खरीदारी जैसी आदतें भी व्यवहार संबंधी लत के रूप में सामने आ रही हैं। इनके उपचार में व्यवहार चिकित्सा, समय प्रबंधन, डिजिटल अनुशासन, भावनात्मक संतुलन और परिवार की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

दोबारा नशे से बचाव

नशा छोड़ने के बाद भी कभी–कभी व्यक्ति फिर से उसकी ओर आकर्षित हो सकता है। इसे असफलता नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उपचार को और मजबूत करने का अवसर समझना चाहिए। नियमित परामर्श, स्वस्थ दिनचर्या, सकारात्मक मित्रों का साथ, तनाव प्रबंधन और परिवार का सहयोग लंबे समय तक नशामुक्त जीवन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

करुणा और सहयोग की आवश्यकता

नशे से जूझ रहे लोगों को तिरस्कार या दंड की नहीं, बल्कि सहानुभूति, सम्मान और उचित उपचार की आवश्यकता होती है। समाज, परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोग व्यक्ति के पुनर्वास को आसान बनाता है। नशे को अपराध नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समझना समय की आवश्यकता है।

भविष्य की दिशा

तंत्रिका विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक और व्यक्तिगत चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे शोध नशा मुक्ति उपचार को और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। भविष्य में ऐसे उपचार विकसित हो रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार अधिक सटीक और सफल होंगे।

नशे की लत जीवन का अंत नहीं है। सही समय पर उपचार, मजबूत इच्छाशक्ति, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति को नई शुरुआत करने का अवसर दे सकता है। नशा मुक्ति की हर छोटी सफलता एक स्वस्थ, सम्मानजनक और आशापूर्ण जीवन की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। ❑❑

(डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन और बलिदान से देश को दिए प्राण

डां श्यामाप्रसाद मुखर्जी ऐसे महान देशभक्त थे जिन्होंने राष्ट्र के चरमोत्कर्ष, एकता और अखण्डता की यज्ञवेदी पर अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह एक साथ ही शिक्षाविद्, लेखक, सासंद, राजनीतिज्ञ और मानवतावादी कट्टर देशभक्त थे। इन्होंने विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की और शीध्र ही एक प्रख्यात शिघ्क्षाविद् और प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी इस उपलब्धि को मान्यता उस समय प्राप्त हुई जब 1934 में कलकत्ता विश्विद्यालय के कुलपति नियुक्त होने वालों में वह सबसे कम आयु के थे। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के निर्माताओं में से थे।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक डां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे उन नेताओं में से थे, जो खुद आगे आकर जोखिम झेलते हैं। उनके लिए भारत प्रथम था और भारत की अखण्डता और वैभव ही प्रमुख लक्ष्य। जान दे दी, पर कश्मीर जाने नहीं दिया। मंत्रिमंडल को ठोकर मार दी, लेकिन सिंद्धातों से समझौता नहीं किया। हॉ, मैं हिन्दू हूॅ इस देश का राष्ट्रत्व हिन्दू हैं। यह अटल सत्य हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दू किसी दूसरे मजहब या उपासना पद्धति के विरूद्ध हैं। ऐसा होता तो इतिहास कुछ और ही होता। कश्मीर हर हिन्दुस्तानी का हैं। हर दिल में कश्मीर के लिए दर्द उठना चाहिए जो हनीफुद्दीन और अजय आहूजा के दिलों में उठा।

डॉ. मुखर्जी ने अपने जीवन और अपने बलिदान, दोनों से ही इस देश को प्राण दिए। उनके लिए भारतीय होने का अर्थ राजनीति के कपट जाल में फॅसना नहीं, वरन् उस कपट जाल को तोडना था। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि आज जो पंजाब और बंगाल का हिस्सा भारत में दिखता हैं, उसके पीछे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखजी का जुझारूपन

डॉ. मुखर्जी ने अपने जीवन और अपने बलिदान, दोनों से ही इस देश को प्राण दिए। उनके लिए भारतीय होने का अर्थ राजनीति के कपट जाल में फॅसना नहीं, वरन् उस कपट जाल को तोडना था।

– हेमेन्द्र क्षीरसागर

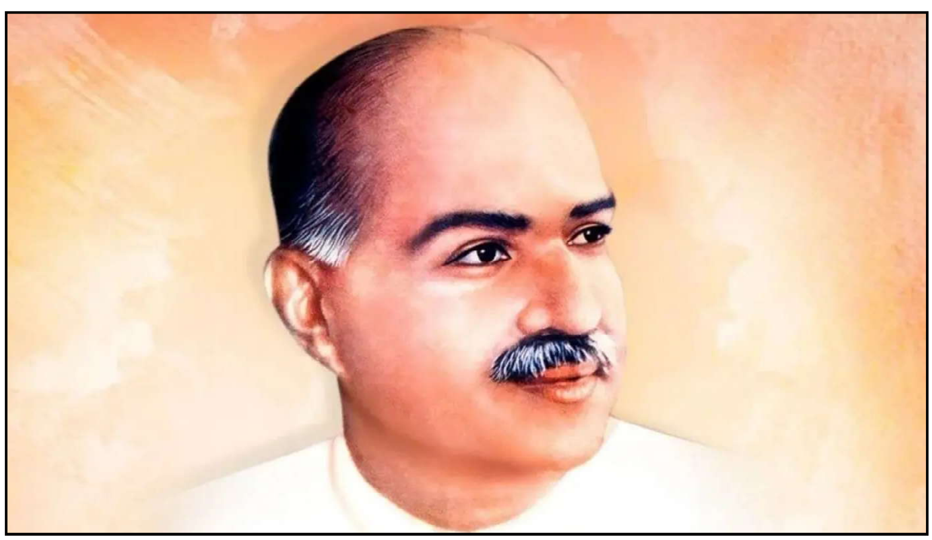

और आंदोलन मुख्य कारण रहे हैं। डॉ. मुखर्जी के वह शब्द इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जब उन्होंने कहा था, 'कांग्रेस ने हिन्दुस्तान का बॅटवारा किया और मैंने पाकिस्तान का।' इस देश का दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्र, किन्तु खंडित भारत की कमान उस व्यक्ति के हाथों में सौंपी गई, जिसे भारतीयता एवं हिन्दुत्व से चिढ थी और स्वयं को देश का अंतिम ब्रिटिश शासक कहलाने में गर्व का अनुभव करता था।

श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने देखा कि विभाजन की भीषण त्रासदी झेलकर जो हिन्दु भारत पहुॅच रहे हैं और जो पाकिस्तान में रह गए हैं, उनके प्रति पंडित नेहरू बेहद उपेक्षपूर्ण और बहुत हदतक निर्मम नीति अपना रहे हैं। इस बिन्दु पर सरदार पटेल और पं. नेहरू में गम्भीर मतभेद पैदा हो गए थे। सरदार पटेल तो यहॉ तक चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान से कुछ जमीन ले लेनी चाहिए। भले ही इसके लिए सशस्त्र पुलिस कार्यवाही ही क्यों न करनी पडे पं. नेहरू ने लियाकत अली से समझौताकर हिन्दुओं के भविष्य को पूरी तरह पाकिस्तानी दरिन्दों के हाथों में छोड दिया। यह देखकर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आगबबूला हो उठे और उन्होंने उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। अपना त्यागपत्र देते समय उन्होंने इसके पीछे के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया जो आज भी ऐतिहासिक तथा प्रेरणप्रद एक दस्तावेज के रूप में माना जाता हैं।

संकल्पित, मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देने के बाद डॉ. मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। लेकिन वह जल्दी ही समझ गए कि प्रतिपक्ष की प्रभावी भूमिका निभाने के लिए संगठित पार्टी बनाना जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से वह प्रतिपक्ष के राजनीतिक मंच के गठन की संभावनाओं को तलाशने की ओर अग्रसर हुए। राष्ट्रीय

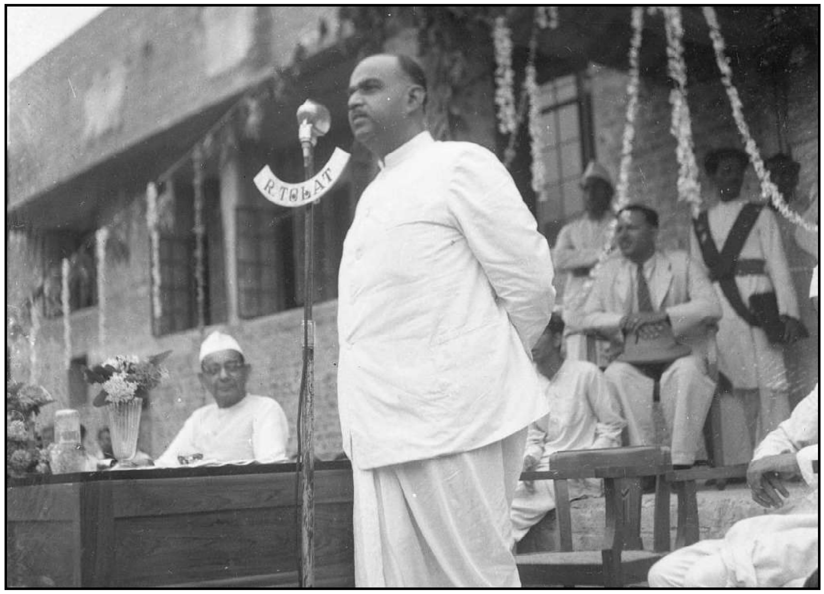

स्वयंसेवक संघ भी किसी सशक्त व्यक्तित्व के नेतृत्व में राजनीतिक दल प्रारंभ किए जाने की जरूरत महसूस कर रहा था। डॉ. मुखर्जी और स्वयंसेवक संघ दोनों ही जिस बात की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। वह समान थी और इसी में से अक्टूबर, 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्‌भव हुआ जिसके संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।

दो वर्ष बाद 1953 में डॉ. मुखर्जी को अपने जीवन में बडी चुनौती का समना करना पडा। जम्मू और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की पृथकतावादी राजनीतिक गतिविधियों से उभरी अलगाववादी प्रवृत्यिां 1952 तक जोर पकडने लगी थीं, जिससे राष्ट्रीय मानस विक्षुब्ध हो उठा। डॉ. मुखर्जी ने प्रजा परिषद् के सत्याग्रह को समर्थन दिया जिसका उद्देष्य जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झण्डा था, अलग संविधान था और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था।

डॉ. मुखर्जी ने जोरदार नारा बुलन्द किया थाः '' एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त कियाः या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा।'' अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में नेहरू सरकार और श्रीनगर में शेख अब्दुला की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया और पं. नेहरू से कहा कि वे जम्मू जरूर जाएंगे और बिना 'परमिट' के जाएंगे।

बलिवेदी

11 मई को रावी नदी पार करते समय ही लखनपुर में डॉ. मुखर्जी को गिरफ्तार कर श्रीनगर जेल ले जाया गया। 40 दिन तक न उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और न अन्य बुनियादी सुविधाएं दी गई। भारत का यह शेर श्रीनगर की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून 1953 को चिरनिद्रा में सो गया। श्रद्धांजलि स्वरूप नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू–कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी। यह ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम था। ❏❏

(हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार, बालाघाट, मप्र)

देश की आन-बान-शान के लिए जरूरी है स्वदेशीः अरूण ओझा

स्वदेशी केवल आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक पहचान, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि यदि भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है तो उत्पादन, उपभोग और रोजगार के क्षेत्र में स्वदेशी मॉडल को मजबूत करना होगा।

उक्त बातें स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व राष्ट्रीय सह—संयोजक श्री अरूण ओझा ने प्रांतीय विचार वर्ग के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में चिार प्रकट करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विदेशी उत्पादों और बाहरी आर्थिक प्रभावों पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि स्थानीय उत्पादन, घरेलू उद्योग और छोटे उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए। उनका मानना था कि जब नागरिक स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरी तरह साकार हो सकेगा।

भागलपुर में स्वदेशी जागरण मंच के दक्षिण बिहार प्रांत द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रांतीय विचार वर्ग आयोजित हुआ। शहर के डोकानिया स्मृति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्योग जगत से जुड़े लोगों और संगठन पदाधिकारियों ने भाग लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी विचारधारा को समाज के बीच और अधिक मजबूत करना, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देना तथा आर्थिक और सामाजिक स्तर पर स्वदेशी सोच को जन—जन तक पहुंचाना रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और स्वदेशी विचारधारा के प्रमुख प्रेरणा स्रोत दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उद्घाटन सत्र के दौरान देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत वातावरण देखने को मिला।

कार्यक्रम का प्रारंभ सामूहिक रूप से वंदे मातरम् के गायन के साथ हुआ, जिसने पूरे सभागार में राष्ट्रीय चेतना और उत्साह का माहौल बना दिया। इसके बाद दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और उन्हें इस विचार वर्ग के उद्देश्यों तथा आगामी सत्रों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्थानीय उद्योगों और कुटीर उद्यमों के महत्व पर भी विशेष चर्चा की। उनका कहना था कि भारत के गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में ऐसी अपार संभावनाएं मौजूद हैं जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति दे सकती हैं। वक्ताओं ने युवाओं की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि आज की युवा पीढ़ी तकनीक, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में नई संभावनाएं तैयार कर रही है। यदि युवा स्वदेशी सोच को अपनाकर स्टार्टअप, स्थानीय उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा दें, तो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल सकती है। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक प्रशिक्षण और वैचारिक स्पष्टता पर भी जोर दिया गया।

संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का उद्देश्य केवल विचारों का प्रचार करना नहीं है, बल्कि समाज में व्यवहारिक परिवर्तन लाना भी है। यदि लोग अपने दैनिक जीवन में छोटे—छोटे स्तर पर भी स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना शुरू करें, तो इसका बड़ा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई।

दो दिवसीय इस विचार वर्ग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर अलग—अलग सत्र आयोजित किए जाने की जानकारी भी दी गई। इनमें एकात्म मानव दर्शन, स्वदेशी चिंतन, विकास और विरासत के बीच संतुलन, वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां, स्वरोजगार, जैविक कृषि, पर्यावरण संरक्षण और संगठन विस्तार जैसे विषय शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा गया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। जब गांव और छोटे शहर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तभी देश की समग्र प्रगति संभव होगी।

समापन सत्र में सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि इस विचार वर्ग की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब यहां प्राप्त विचार और प्रेरणा समाज के बीच पहुंचें और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बनें। ❑

सशक्त और स्वावलंबी बनाने का मार्ग है स्वदेशीः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच के दो दिवसीय विचार वर्ग का शुभारंभ माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नौगावां में नितिन स्पिनर्स के चेयरमैन नितिन नौलखा के मुख्य आतिथ्य व प्रांत कार्यवाहक डॉ. शंकर लाल माली की अध्यक्षता में हुआ। उद्घाटन सत्र में अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा कि स्वदेशी का महत्व केवल सामान क्रय करने तक ही सीमित नहीं है। स्वदेशी भारत को समर्थए शक्तिशाली और वैभवशाली बनाने का अधिष्ठान है।

मंच पर सुरेश कुमार अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघए डॉक्टर भगवती प्रकाश अखिल भारतीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच एवं राष्ट्रीय समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान एवं सतीश कुमार आचार्य राजस्थान क्षेत्र संयोजक स्वदेशी जागरण मंच पर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि दिनेश नौलखा ने 1993 में स्थापित नितिन स्पिनर्स की पृष्ठभूमि और आए हुए चुनौतियों और उसके संघर्षपूर्ण समाधान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आज पूरा देश चीन से सामान मंगाता है और हम चीन में निर्यात करते हैं। गुणवत्ता कार्य को बढ़ाने का आधार है। अपने कार्य की गुणवत्ता उद्यमिता में प्रकट होनी चाहिए।

डॉ. शंकर लाल माली ने कहा कि कार्यकर्ता में कार्य बड़ा हो जाए कर्ता भाव खत्म होता जाए। यही सच्ची साधना होती है। अपना हम अपना अहम धीरे.धीरे क्षीण होता चला जाना चाहिए और कार्य बड़ा होता जाना चाहिए द्य अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ भगवती प्रकाश शर्मा ने बताया कि आज भी हम वैश्विक उत्पादन के आंकड़ों में बहुत नीचे हैं। विश्व का 60 प्रतिशत से अधिक उत्पादन तो केवल तीन देशों में ही होता है जिसमें अमेरिका 16 प्रतिशत चीन 38 प्रतिशत और जापान 6 प्रतिशत है।

द्वितीय सत्र प्रांत संयोजक डॉ. संत कुमार ने संगठन की रचना एवं दायित्व बोध पर व्याख्यान दिया। पर्यावरण व जैविक खेती विषय पर प्रांत पर्यावरण प्रमुख महेश नवहाल ने विचार व्यक्त किए। जैविक खेती अपनाने से न केवल खेत की मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी वरन् विभिन्न रोगों से जूझ रही मानवता को भी राहत मिलेगी। तृतीय सत्र में डॉ. कृष्ण अवतार गोयलए डॉ. ज्योति वर्मा एवं डॉ संत कुमार ने संगठन के तकनीकी विषय लिए।

चतुर्थ सत्र में डॉ राजकुमार चतुर्वेदी ने युवा जनसंख्या समृद्धि का आधारए घटती फर्टिलिटी की दर पर अपना विषय प्रतिपादन किया। विचार वर्ग में चित्तौड़ प्रांत के 14 जिलों के विभिन्न दायित्वधारी भाग ले रहे हैं। व्यवस्थाओं के समन्वय में डॉक्टर बी एल जागेटियाए राजेंद्र सिंह गहलोतए अजय कुमार दरडाए डॉ देवीलाल साहूए त्रिलोक क्षोत्रियए जानकी नन्दन मालीए रवि कोहलीए महावीर जांगिड़ए दिनेश शर्माए राजू बागरियाए अक्षय जोशीए मुकेश जांगिड़ए सौरभ आर्य आदि लगे हैं।

स्वदेशी के सिद्धांतों से ही होगी भारत की समृद्धि : सतीश कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संगठक सतीश कुमार तथा त्रिप्रांतीय संगठक विनय कुमार का लुधियाना प्रवास के दौरान गौरव अरोड़ा के निवास पंहुचने पर परम्परागत अंदाज में स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को उनसे आत्मीय भेंट एवं प्रेरणादायी संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पूर्व दोनों वरिष्ठ पदाधिक्कारियों ने लुधियाना के विभिन्न स्थानों पर आयोजित बैठकों में सहभागिता करते हुए स्वदेशी विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाने का आहवान किया। उन्होने कहा भारत की आर्थिक मजबूती और समृद्धि का मार्ग स्वदेशी के सिद्धांतों से होकर गुजरता है। देशवासियों को अधिक से अधिक भारतीय उत्पादों का उपयोग करना चाहिए तथा स्थानीय उद्योगों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आर्थिक राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएगा।

गौरव अरोड़ा ने युवाओं, व्यापारियों और उद्यमियों से भी स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन में सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान किया। बैठक के दौरान स्वदेशी, आर्थिक आत्मनिर्भरता, उद्यमिता संवर्धन और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपस्थित लोगों ने दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन, अनुभव एवं राष्ट्रहित के प्रति समर्पित दृष्टि कोण को अत्यंत प्रेरणादायी बताया।

स्वदेशी ऊर्जा एवं खाद आत्मनिर्भरता अभियान

स्वदेशी शोध संस्थान द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली में स्वदेशी ऊर्जा एवं खाद आत्मनिर्भरता अभियान" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में देशभर से 120 से अधिक नीति–निर्माताओं, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, बायोगैस विशेषज्ञों तथा विभिन्न सरकारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

कार्यशाला का शुभारंभ आइआइटी दिल्ली के उप निदेशक प्रो. अरविंद कुमार नेमा के स्वागत उद्बोधन से हुआ। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास तथा ग्रामीण भारत में बायोगैस तकनीकों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार की पहलों को समय की आवश्यकता बताया। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने "स्वदेशी ऊर्जा एवं खाद आत्मनिर्भरता अभियान की राष्ट्रीय भूमिका" विषय पर अपने विचार रखते हुए देश में विकेन्द्रीकृत ऊर्जा मॉडल अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं प्रो. वीरेन्द्र कुमार विजय, राष्ट्रीय समन्वयक, उन्नत भारत अभियान एवं समन्वयक, बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र, आइआइटी दिल्ली ने ऊर्जा एवं खाद आत्मनिर्भरता के लिए बायोगैस ऊर्जा एवं जैविक खाद के महत्व पर जानकारी दी।

कार्यशाला में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के पूर्व अनुसंधान वैज्ञानिक प्रो. होयसला एन. चाणक्य, बायोगैस विशेषज्ञ प्रो. दीपक शर्मा, तथा उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी ने भी अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एवं विकेन्द्रीकृत बायोगैस संयंत्रों के विस्तार, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया। पद्मश्री भारत भूषण ने कार्यशाला के दौरान अभियान को सफल बनाने की रणनीति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने जनभागीदारी, तकनीकी सहयोग, संस्थागत समन्वय तथा किसानों की सक्रिय सहभागिता को इस अभियान की सफलता का प्रमुख आधार बताया।

उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि लोग बायोगैस संयंत्र को केवल एक तकनीक या परियोजना न मानें, बल्कि उसे अपने परिवार और जीवन का अभिन्न हिस्सा समझते हुए उससे आत्मीय एवं भावनात्मक रूप से जुड़ें।

'मैं भी स्वदेशी समर्थक' अभियान से कार्यकर्ता विस्तार पर जोर

सुल्तानपुर में स्वदेशी जागरण मंच के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक कार्यकारी बैठक वरिष्ठ आयाम प्रमुख अधिवक्ता सुरेंद्र की अध्यक्षता में पर्यावरण पार्क में संपन्न हुई। इस बैठक में 'स्वावलंबी भारत अभियान' को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु पूर्णिमा महापर्व की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त से 'मैं भी स्वदेशी समर्थक अभियान' शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों, प्रमुख संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों, सामाजिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को स्वदेशी जागरण मंच से जोड़ने के लिए व्यापक जन–जागरण अभियान चलाया जाएगा।

प्रांत सह प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र द्विवेदी ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच की सक्रिय टोली अब बूथ स्तर तक कार्य कर रही है। आगामी अभियान के दौरान कार्यकर्ता टोलियां बनाकर जनपद के प्रत्येक ब्लॉक और बूथ तक पहुंचेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल सदस्यता बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों को स्वावलंबन से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

प्रांत सह महिला समन्वय प्रमुख नीलम त्रिपाठी ने कहा कि जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन से जोड़ना समय की आवश्यकता है। कार्यकर्ता सरकार की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी युवाओं तक पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें। विभाग संयोजक राजीव तिवारी ने भी कहा कि यह अभियान युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करेगा, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

विभाग महिला प्रमुख शालिनी त्रिपाठी ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच का प्रत्येक कार्यकर्ता इसके व्यापक प्रचार–प्रसार में जुट गया है। जिला संयोजक गंगा शरण ने कहा कि सुल्तानपुर जिले की पूरी टीम इस अभियान को सफल बनाने के लिए तैयार है। 1 अगस्त से कार्यकर्ता टोलियां बनाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे और लोगों को अभियान के प्रति जागरूक कर मंच से जोड़ेंगे।

बैठक का संचालन जिला महिला प्रमुख रश्मि शुक्ला ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ता आशीष तिवारी, जनार्दन यादव, दीपक मिश्रा, शशि जी, हेमलता सहित स्वदेशी जागरण मंच के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ❑❑

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/sultanpur/news/sultanpur-swadeshi-jagran-manch-abhiyan-meeting-update-138482914.html

स्वदेशी गतिविधियां

जिला विचार/प्रशिक्षण वर्ग

सचित्र झलक

बीजापुर, छत्तीसगढ़

ओडिशा पूर्व

गांधी नगर, दिल्ली

गुजरात

गोवलपारा, उत्तरी असम

जालंधर, पंजाब

पाली, जोधपुर

त्रिपुरा

देवघर, झारखंड

शिमला, हिमाचल प्रदेश

स्वदेशी पत्रिका   डाक तिथि 15–16 जून 2026
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

जिला विचार/प्रशिक्षण वर्ग

सचित्र झलक

भागलपुर, बिहार

भाग्यनगर, हैदराबाद

जम्मू

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

उत्तर 24 परगना, दक्षिण बंग

अत्तूर, तमिलनाडू

अमरोहा, मेरठ

देहरादून, उत्तराखंड

ओडिशा पश्चिम

कन्नौज, कानुपर

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती